वर्ष 13 • अंक 10 • 12+44 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

गुरुवार 27 फरवरी 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

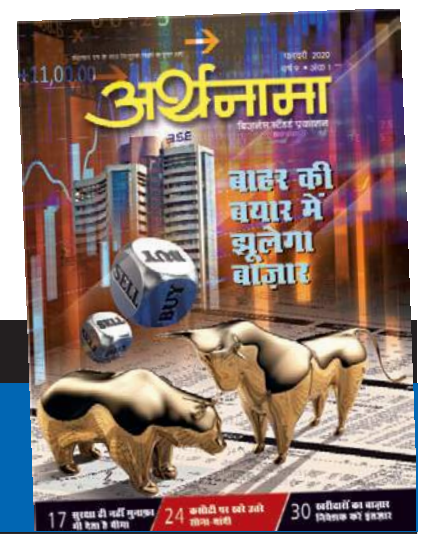

पृष्ठ 6

कोरोनावायरस से इस्पात की मांग प्रभावित

आज के अंक के साथ 'अर्थनामा' निःशुल्क

डॉलर रु. 71.70 ▼ 20 पैसे | यूरो रु. 78.00 ▲ 10 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 42484 ▼ 153 रुपये | सेंसेक्स 39889.00 ▼ 392.20 | निफ्टी 11678.50 ▼ 119.40 | निफ्टी फ्यूचर्स 11699.30 ▲ 20.80 | ब्रेंट क्रूड 53.20 डॉलर ▼ 01.10 डॉलर

एक नज़र

कोरोना का कहर जारी, सेंसेक्स 40,000 से नीचे

कोरोनावायरस बीमारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले वित्तीय प्रभाव की चिंताओं के बीच देसी शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार चौथे दिन गिरावट रही। कोरोनावायरस अब कुछ नए देशों तक भी पहुंच चुका है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत बिगड़ने का अंदेशा बढ़ गया है। वैश्विक बाजार में गिरावट के बीच सेंसेक्स 392 अंक लुढ़क कर 39,888.96 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 119.40 अंक फिसल कर 11,678.50 के स्तर पर बंद हुआ। कारोनावायरस फ्रांस, ईरान, दक्षिण कोरिया और इटली जैसे देशों में भी पहुंच चुका है।

बीमा मध्यस्थता नीति में हुए संशोधन

उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने बीमा मध्यस्थता में स्वचालित तरीके से 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति देने के लिए 2017 की समेकित प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति में संशोधन किए हैं। अब इस नीति में बीमा ब्रोकर, पुनर्बीमा ब्रोकर, बीमा सलाहकार, कंपनी एजेंट, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेक्षक एवं क्षति आकलनकर्ता भी शामिल किए गए हैं। पृष्ठ 4

नए ऑडिट नियम कंपनियों को धोखाधड़ी से बचाएंगे

अंकेक्षक समुदाय के बीच वित्तीय अनुशासन लाने के लिए सरकार ने अंकेक्षकों से कहा है कि वे कंपनी की तरफ से दिए गए हर तरह के कर्ज की विस्तृत जानकारी मुहैया कराए, चाहे वह व्हिसलब्लोअर की शिकायतों पर आधारित हो या अंकेक्षण की आंतरिक व्यवस्था के आधार पर। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कंपनीज अडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 अधिसूचित कर दिया है, जो अंकेक्षकों की तरफ से जांच-परख (ड्यू डिलिजेंस) और डिस्क्लोजर में इजाफे के लिए है। साथ ही कंपनी की पारदर्शी वित्तीय स्थिति ऐसे समय में सामने रखने की बात है जब अंकेक्षक नियामकीय कोप का सामना कर रहे हैं। पृष्ठ 3

एचयूएल-जीएसके विलय को मंजूरी मिली

राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) के चंडीगढ़ पीठ ने बुधवार को ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन (जीएसके) कंज्यूमर और हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के विलय की योजना को मंजूरी दे दी। विश्लेषकों का कहना है कि यह मंजूरी मिलने से दोनों कंपनियों के बीच विलय का रास्ता साफा हो गया है और अगले कुछ सप्ताहों में इसकी घोषणा होने की संभावना है। एनसीएलटी-मुंबई ने सितंबर में इस विलय को अपनी मंजूरी दी थी। एचयूएल के साथ जीएसके कंज्यूमर का विलय जीएसके कंज्यूमर के प्रत्येक शेयर के लिए 4.39 एचयूएल शेयरों के विनिमय अनुपात पर आधारित होगा।

अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर

हुरुन की विश्व के धनी व्यक्तियों की सूची में शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय मुकेश अंबानी हैं। वह इस सूची में 9वें पायदान पर रहे हैं। एमेजॉन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस लगातार तीसरे साल शीर्ष पायदान पर रहे हैं। मुकेश अंबानी एशिया में भी सबसे धनी हैं। उनकी संपत्ति में 24 फीसदी या 13 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। दुनिया के सबसे धनी 100 लोगों में भारतीय बैंकर उदय कोटक भी शामिल हो गए हैं। पृष्ठ 12

वोडाफोन ने फिर लगाई गुहार

संकटग्रस्त कंपनी ने की जीएसटी रिफंड एजीआर बकाये में समायोजित करने की मांग

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 26 फरवरी

- वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग को लिखा पत्र
- 8,000 करोड़ रुपये का जीएसटी फंड समायोजित करने की मांग
- एजीआर भुगतान कार्यक्रम में राहत का अनुरोध
- दूरसंचार क्षेत्र पर नियामकीय बोझ को व्यावहारिक बनाने का अनुरोध
- दूरसंचार क्षेत्र इस समय जूझ रहा गंभीर संकट से

वित्तीय संकट से जूझ रही दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपने 8,000 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड को एजीआर बकाये में समायोजित करने की मांग की है। एक अधिकारी ने बताया कि कंपनी ने दूरसंचार विभाग को एक पत्र लिखकर यह मांग की है। कंपनी ने साथ ही सरकार से एजीआर बकाये के भुगतान के कार्यक्रम को भी टालने का अनुरोध किया है।

कंपनी का कहना है कि उसकी वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है और उसके क्रेडिट को एजीआर बकाये में समायोजित किया जाए। कंपनी ने पत्र में लिखा है कि अगर सरकार करीब 8,000 करोड़ रुपये के जीएसटी क्रेडिट को एजीआर बकाये में समायोजित करने की अनुमति देती है तो वह स्व-आकलन की शेष मूल राशि का निपटान कर सकती है। कंपनी ने साथ ही सरकार से ब्याज, जुर्माने और जुर्माने पर ब्याज की शेष राशि का किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया है।

सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके तहत कंपनी को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस फीस का किस्तों में भुगतान करने की अनुमति देकर राहत दी जा सकती है। वोडाफोन आइडिया को उस समय बड़ा झटका लगा था जब उच्चतम न्यायालय ने उसे बकाये के भुगतान में राहत देने से इनकार कर दिया था। कंपनी अब तक 3,500 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है और स्व-आकलन के मुताबिक कंपनी को 23,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इसमें से 7,000 करोड़ रुपये मूलधन है। कंपनी पर दूरसंचार विभाग का 54,000 करोड़ रुपये बकाया है। कंपनी ने कहा, 'दूरसंचार उद्योग की वित्तीय मजबूती बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि इस क्षेत्र पर नियामकीय लागत बोझ को तुरंत व्यावहारिक बनाया जाए।' कंपनी ने अपने बकाये के भुगतान के लिए दूरसंचार विभाग से तीन साल की मोहलत मांगी है और साथ ही लाइसेंस फीस 8 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी करने का अनुरोध किया है।

2016 में सरकार ने भविष्य की नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क 3 फीसदी निर्धारित किया था और सभी मौजूदा स्पेक्ट्रम आवंटनों के लिए एक भारांकित औसत फॉर्मूला मंजूर किया था। वोडाफोन आइडिया ने स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क को 3 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी करने की मांग की है। कंपनी ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय संकट की मुख्य वजह यह है कि कड़ी प्रतिस्पर्द्धा के कारण दूरसंचार सेवाओं की कीमत लागत से कम है। 2019 में बाजार कीमतों में कुछ इजाफा हुआ लेकिन यह लागत वसूलने के लिए पर्याप्त नहीं है। आधार मूल्य नियमन के बिना इसमें और बढ़ोतरी संभव नहीं है। फिक्स्ड कनेक्टिविटी चार्ज, आउटगोइंग वॉयस और डेटा प्राइस के साथ आधार मूल्य को तुरंत लागू किया जाना चाहिए।

पिछले सप्ताह वोडाफोन आइडिया के शीर्ष अधिकारियों ने एजीआर बकाये में राहत के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की।

उच्चतम न्यायालय ने 14 फरवरी को एजीआर बकाये की भुगतान योजना में राहत देने के लिए दायर दूरसंचार कंपनियों की संशोधित याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इससे पहले न्यायालय ने पिछले साल 24 अक्टूबर को अपने फैसले में दूरसंचार विभाग की एजीआर की परिभाषा को सही करार देते हुए दूरसंचार कंपनियों को तीन महीने के भीतर अपने बकाये का भुगतान करने को कहा था।

बैंक शाखा स्तर पर मजबूत करें संपर्क

सोमेश झा
नई दिल्ली, 26 फरवरी

- अच्छी नहीं रेटिंग एजेंसियों पर ज्यादा निर्भरता
- तकनीक के अपने फायदे लेकिन ग्राहक चाहे आत्मीयता
- व्यक्तिगत संपर्क और डेटा के बीच तालमेल की जरूरत
- शाखा स्तर के कर्मचारियों की समस्याएं सुनें अधिकारी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकारी बैंकों को अगर अपने कामकाज में सुधार करना है तो उन्हें ग्राहकों के साथ शाखा स्तर पर आत्मीय संपर्क की पुरानी व्यवस्था की ओर लौटना चाहिए। एक तरफ उन्होंने यह बात कही और दूसरी ओर बैंकिंग में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाने के लिए नए सुधार उपायों की घोषणा की।

वित्त मंत्री ने बैंकों के शीर्ष अधिकारियों को आगाह किया कि उन्हें ग्राहकों के क्रेडिट स्कोर के लिए रेटिंग एजेंसियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, 'मैं जो कहूंगी वह आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब शाखा के स्तर पर ग्राहकों के साथ पहले ही तरह संपर्क नहीं रह गया है। हालांकि डेटा एनालिटिक्स और व्यापक डेटा समय की मांग है क्योंकि इसके अपने फायदे हैं लेकिन शाखा के स्तर पर ग्राहक आपसे थोड़ा व्यक्तिगत आत्मीयता की उम्मीद रखता है।'

सीतारमण ने कहा कि बैंकों को रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग को एक संकेतक के रूप में लेना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा, 'क्या किसी अधिकारी ने कहा है कि आपको आंख मूंदकर रेटिंग एजेंसियों की रेटिंग को मानना चाहिए।' उन्होंने कहा कि बैंक काफी हद तक क्रेडिट रेटिंग पर निर्भर हो गए हैं और इस कारण कई बार उन्होंने ग्राहकों को समझने में गलती की है।

उन्होंने कहा, 'व्यक्तिगत संपर्क और डेटा का बेहतर तालमेल करने की जरूरत है।' वित्त मंत्री ने शीर्ष अधिकारियों को शाखा स्तर के कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने और उन्हें सरकार की योजनाओं से अवगत कराने का सुझाव दिया। अपने कर्मचारियों की बात सुनें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक नकदी का प्रवाह नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वह 2 अप्रैल को संसद का सत्र खत्म होने के बाद बैंकों की जिला स्तर की शाखाओं के कर्मचारियों के साथ नियमित बैठक करेंगी और उनकी शिकायतें सुनेंगी।

भाषण के बाद सीतारमण ने सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्याधिकारियों के साथ दो बैठकें की। इनमें से एक सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों के बारे में और दूसरी बैंकिंग के अन्य क्षेत्रों के बारे में थी।

बैठक में सीतारमण ने बैंकरों से क्रेडिट के प्रवाह पर जोर देने को कहा। हालांकि बैंकरों का कहना था कि अर्थव्यवस्था में मांग की कमी है। वित्तीय सेवा सचिव बनने जा रहे देवाशीष पांडा ने बैंकों से कहा कि उन्हें क्रेडिट बढ़ाने के लिए कुछ रणनीति बनानी चाहिए। वे यह कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि मांग की समस्या है। उन्होंने कहा, आपको आपूर्ति की ओर जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने यही बात कही है। संवाददाता सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने एमएसएमई ऋण के पुनर्गठन के लिए बैंकों के साथ एक समीक्षा बैठक की है।

सस्ते फोन लाएगी जियो

सस्ते 4जी मोबाइल फोन बनाने के लिए विनिमाता और रिलायंस जियो के बीच बातचीत चल रही है। जियो 2,000 -3,000 रुपये कीमत वाले 4जी स्मार्टफोन के लिए बड़ा ऑर्डर देना चाहती है। लावा मोबाइल के निदेशक एस एन राय ने कहा कि जियो ने उनके साथ भी ऐसी चर्चा की है। सूत्रों के अनुसार, जियो बड़े पैमाने पर 2जी ग्राहकों को 4जी नेटवर्क पर लाना चाहती है। वह प्रतिस्पर्धी दूरसंचार कंपनियों से 2जी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ाना चाहती है। पृष्ठ 2

एयरटेल भुगतान में सक्षम

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने बुधवार को कहा कि निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के 5 पांच अरब डॉलर के सांविधिक बकाया चुकाने की वित्तीय क्षमता है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने इसी महीने दूरसंचार कंपनियों से बकाया रकम चुकाने संबंधी उसके 24 अक्टूबर, 2019 के फैसले का सख्ती से अनुपालन करने का सख्त निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय अपने फैसले में दूरसंचार विभाग की समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को उचित ठहराया था। पृष्ठ 2

फ्लिपकार्ट सौदे पर कर से जुड़ी चुनौती जारी

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 26 फरवरी

- विदेशी निवेशक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी पहुंचे
- कुछ निवेशकों को आय कर विभाग ने नहीं दिया लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट

वॉलमार्ट-फ्लिपकार्ट सौदे के लिए कर से जुड़ी परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ई-वाणिज्य कंपनी फ्लिपकार्ट के कुछ विदेशी हिस्सेदारों ने सौदे के बाद पूंजीगत लाभ पर कराधान से संबंधित स्थिति स्पष्ट करने की मांग करते हुए इंडियाज अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स (एएआर) का दरवाजा खटखटाया है। समझा जा रहा है कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट के विदेशी अंशधारकों सॉफ्टबैंक, नैस्पर्स, ऐसल पार्टनर्स के करों में कमी की है और इन अंशधारकों द्वारा अर्जित पूंजीगत लाभ से संबंधित विदहोल्डिंग टैक्स का भुगतान किया था। विदेशी अंशधारकों ने वॉलमार्ट के इस कदम के बाद एएआर पहुंचे हैं।

विदहोल्डिंग टैक्स स्रोत पर काटा गया कर होता है। कुछ देश ब्याज या देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति को भुगतान हुए लाभांश पर लगाते हैं। एएआर कानूनी रूप से स्थापित इकाई है, जिसका निर्णय याची और सरकारी इकाइयों दोनों पर लागू होता है। आयकर अधिनियम के तहत एक विदेशी कंपनी या भारतीय करदाता भारत में प्रस्तावित कराधान से जुड़े मुद्दे पर कराधान संबंधित राहत पा सकता हैं। इस पूरे मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने कहा, 'एएआर में इस महीने कुछ और याचिकाएं भी आई हैं, इसलिए इस मुद्दे पर अंतिम आदेश आने में चार से पांच महीने का समय लग सकता है।'

इस पूरे मामले पर सॉफ्टबैंक के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, वहीं ऐसल और वॉलमार्ट को मंगलवार को भेजे ई-मेल का कोई जवाब नहीं आया। इनमें कुछ विदेशी निवेशकों ने कर विभाग से आयकर कानून के प्रावधान 197 के तहत लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेशन की मांग की थी। इस मांग पर अब भी विचार चल रहा है।

आयकर प्रावधानों के तहत कोई खरीदार लेनदेन का सबूत देकर अधिकारियों से विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट की मांग कर सकता है कम कर का या बिल्कुल भुगतान नहीं करने का लाभ ले सकता है। प्रवासी विक्रेता दोहरे कराधान से जुड़े समझौता का हवाला देकर कमर कम दरों पर कराधान कर सकते हैं। इस पूरे मामले से अवगत एक कर अधिकारी ने कहा,'लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट के प्रावधान के जरिये प्रवासी बिक्री पर मूल्य के बजाय बिक्री के बार अर्जित पूंजीगत लाभ पर कर काटे जाने का लाभ उठा सकते हैं।' सूत्रों का कहना है कि संबंधित कर अधिकारी ने याचिकाओं की जांच की है, लेकिन कई मामलों में वे इनमें मजबूत आधार नहीं पाते हैं।

जेवर हवाईअड्डा से होगी मोटी कमाई

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 26 फरवरी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के 2023 में चालू होने के बाद 30 वर्षों में इससे एक लाख करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।

योगी ने राज्य विधानसभा में दावा किया कि पिछली सरकारों के फैसला नहीं लेने के कारण जेवर परियोजना दो दशकों से लटकी हुई थी। उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार ने विकास का एक मॉडल बनाया है। भूस्वामियों ने स्वेच्छा से हवाईअड्डा परियोजना के लिए अपनी जमीन दी है क्योंकि पिछली सरकार के समय में मुआवजे का एक हिस्सा दलालों की जेब में जाता था।' मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन साल में राज्य में 2.5 लाख करोड़ रुपये का निजी निवेश आया है जिससे 33 लाख लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा, 'पहले कोई भी निवेशक उत्तर प्रदेश आने को तैयार नहीं था, लेकिन हमने इस धारणा को बदल दिया है।'

कर के चक्कर में बरस रहा लाभांश

समी मोडक
मुंबई, 26 फरवरी

इन दिनों दलाल पथ पर लाभांश की बारिश हो रही है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस महीने हरेक दिन एक दर्जन से अधिक कंपनियों ने लाभांश देने की घोषणा की है। कंपनियों के ऐसा करने की एक खास वजह है। 1 फरवरी को पेश बजट के अनुसार अगले वित्त वर्ष से लाभांश कर देनदारी कंपनियों के माथे न रखकर प्रवर्तकों पर डाल दी जाएगी। कारोबारियों का कहना है कि कंपनियां प्रवर्तकों की कर देनदारी कम करने के लिए समय रहते लाभांश का भुगतान कर रही हैं।

इस महीने अब तक करीब 200 कंपनियों ने अंतरिम लाभांश देने की घोषणाएं की हैं। यह तादाद पिछले साल इसी अवधि के दौरान लाभांश घोषित करने वाली कंपनियों के मुकाबले दोगुनी है। इतना ही नहीं, लाभांश वितरण की रकम भी पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक है। बाजार पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि अगली कुछ तिमाहियों के मुनाफा अनुमानों के मद्देनजर कंपनियां ऊंचे अंतरिम लाभांश का भुगतान कर रही है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले और कई कंपनियां लाभांश का भुगतान करेंगी। आम तौर पर अंतिम लाभांश का भुगतान अगले वित्त वर्ष तक खिंच जाता है। कुछ कंपनियां तो मोटे लाभांश का भुगतान कर रही हैं। इनमें बजाज ऑटो (प्रति शेयर 120 रुपये), श्री सीमेंट (110 रुपये प्रति शेयर) और हीरो मोटोकॉर्प (65 रुपये प्रति शेयर) शामिल हैं। इन कंपनियों सहित दूसरी कई अन्य कंपनियों द्वारा किए गए लाभांश भुगतान हाल में उनके द्वारा वितरित भुगतान के मुकाबले कहीं अधिक हैं।

निवेश सलाहकार कंपनी स्प्लिंटिशियन डॉट कॉमे संस्थापक एस पी तुलस्यान ने कहा, 'जितनी कंपनियों ने मोटे लाभांश दिए हैं, उनमें ज्यादातर में प्रवर्तकों की हिस्सेदारी अधिक है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि प्रवर्तकों को फायदा देने के लिए कंपनियां ऐसा कर रही हैं। इन प्रवर्तकों को नए वित्त वर्ष से 40 प्रतिशत से अधिक कर भुगतान करना होगा। मुझे लगता है कि अगले दो हफ्तों में नकदी से लैस कंपनियां लाभांश भुगतान के लिए आगे आएंगी।' वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कंपनियों द्वारा 20.56 प्रतिशत लाभांश वितरण कर समाप्त करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों को लाभांश मिलेगा उनकी आय में इसे जोड़कर उनसे कर लिया जाएगा।

प्रवर्तकों का बोझ घटाने की कवायद

कंपनी	लाभांश(%)*	लाभांश प्रति शेयर	कुल भुगतान (करोड़ रुपये में)
बजाज ऑटो	1,200	120	3,472
श्री सीमेंट	1,100	110	397
हीरो मोटोकॉर्प	3,250	65	1,298
टाइड वाटर ऑयल	1,200	60	21
पेज इंडस्ट्रीज	580	58	65
महाराष्ट्र स्कूटर्स	500	50	57
बजाज होल्डिंग्स	400	40	445

स्रोतः कैपिटालाइन, संकलनः बीएस रिसर्च, *अंकित मूल्य का प्रतिशत

खबरों में रहे स्टॉक

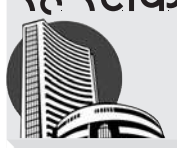

इंडिया सीमेंट्स

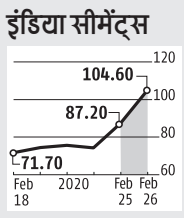

गोपीकिशन दमानी ने खुले बाजार से खरीदी 2.75 फीसदी हिस्सेदारी

₹ 87.20 पिछला बंद भाव
₹ 104.60 आज का बंद भाव
▲ 20.00 %

सनोफी इंडिया

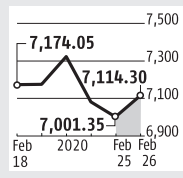

विशेष लाभांश के साथ कुल 349 रुपये प्रति शेयर लाभांश की घोषणा

₹ 7,001.35 पिछला बंद भाव
₹ 7,114.30 आज का बंद भाव
▲ 1.61 %

बंधन बैंक

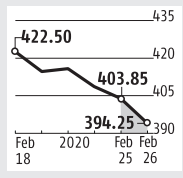

भारतीय रिजर्व बैंक ने नई शाखा खोलने से प्रतिबंध हटाया

₹ 403.85 पिछला बंद भाव
₹ 394.25 आज का बंद भाव
▼ 2.38 %

लार्सन ऐंड टुब्रो

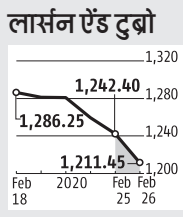

बाजार पूंजीकरण के क्रम में 16वें पायदान पर फिसला

₹ 1,242.40 पिछला बंद भाव
₹ 1,211.45 आज का बंद भाव
▼ 2.49 %

अदाणी ट्रांसमिशन

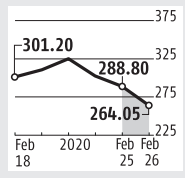

एसऐंडपी बीएसई मिडकैप सूचकांक में सबसे अधिक गिरने वाला शेयर

₹ 288.80 पिछला बंद भाव
₹ 264.05 आज का बंद भाव
▼ 8.57 %

संक्षेप में

क्रिसिल ने ग्रीनविच का अधिग्रहण पूरा किया

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने प्रप्राइटरी बेंचमार्किंग डेटा प्रदाता ग्रीनविच एसोसिएट्स का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इस सौदे की घोषणा 19 दिसंबर, 2019 को की गई थी। क्रिसिल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशु सुयष ने बुधवार को कहा कि ग्रीनविच के अधिग्रहण से क्रिसिल को विभिन्न वित्तीय सेवाओं में वैश्विक बेंचमार्किंग विश्लेषण बाजार का अग्रणी खिलाड़ी बनने की रणनीति में मदद मिलेगी। *भाषा*

टाटा मोटर्स को 500 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी

टाटा मोटर्स के निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी प्राप्त समिति ने निजी नियोजन के आधार पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर 500 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दे दी। कंपनी ने कहा कि यह राशि निजी नियोजन के जरिये 250-250 करोड़ रुपये की दो किस्तों में जुटाई जाएगी। *भाषा*

सस्ते स्मार्टफोन लाएगी जियो

कंपनी की 3,000 रु. से कम कीमत वाले 4जी स्मार्टफोन के लिए विनिर्माताओं संग बात

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 26 फरवरी

रिलायंस जियो के लिए सस्ते 4जी मोबाइल फोन बनाने के लिए विनिर्माताओं और जियो के बीच बातचीत चल रही है। जियो 2,000 से 3,000 रुपये के बीच कीमत वाले 4जी स्मार्टफोन के लिए बड़ा ऑर्डर देना चाहती है।

लावा मोबाइल के निदेशक एसएन राय ने कहा, 'हां, हम उन कंपनियों में शामिल हैं जिनके साथ चर्चा हुई थी। यह एक चुनौती है जिसे हमने स्वीकार किया है। हम कच्चे माल की लागत पर गौर कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि मूल्य के लिहाज से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है अथवा नहीं। यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो हम सब्सिडी के लिए कह सकते हैं।' उन्होंने कहा कि यदि कंपनी जियो के लिए मोबाइल फोन बनाएगी तो खुद अपने ब्रांड नाम से बनाएगी क्योंकि जियो का उद्देश्य इस मूल्य दायरे में 4जी स्मार्टफोन के लिए माहौल तैयार करना है। बातचीत से अवगत सूत्रों के अनुसार, जियो की नजर बड़े पैमाने पर 2जी ग्राहकों को 4जी में लाना है। वह प्रतिस्पर्धी दूरसंचार कंपनियों से 2जी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ाना चाहती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी बाधा गुणवत्ता को लेकर है क्योंकि आमतौर पर 4जी स्मार्टफोन की कीमत 5,000 रुपये से शुरू होती है और ऐसे में 2जी ग्राहकों को 4जी में लाना आसान नहीं दिख रहा है। जियो महीना दर महीना 60 से 90 लाख ग्राहकों को जोड़ रही है। इनमें से करीब 30 लाख ग्राहक उसके 4जी फीचर फोन की बिक्री के जरिये जुड़े हैं। जियो महज 501 रुपये अथवा छह महीने के लिए मुफ्त डेटा एवं वॉइस के साथ 1,095 रुपये में फीचर फोन उपलब्ध करा रही है।

यह पहल कंपनी की द्विआयामी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वृद्धि की अगली लहर में राजस्व और ग्राहक बढ़ाने पर जोर दिया गया है। रिलायंस जियो के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार किया।

प्रतिस्पर्धी नेटवर्क पर अभी भी 50 करोड़ से अधिक ग्राहक 2जी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। जियो ने उन्हें अपने 4जी नेटवर्क पर लाने की योजना बनाई है ताकि वह अपने ग्राहकों की कुल संख्या को मौजूदा 37.5 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ तक पहुंचा सके।

विश्लेषकों का कहना है कि जियो को अपने इस प्रयास में अकेले आगे बढ़ना होगा क्योंकि प्रतिस्पर्धी दूरसंचार कंपनियां अच्छी गुणवत्ता वाले सस्ते स्मार्टफोन के जरिये ग्राहकों को तेजी से अपनी ओर आकर्षित करने पर ध्यान नहीं दे रही हैं। इसका कारण साफ है कि कुछ प्रतिस्पर्धियों के पास देश भर में 4जी नेटवर्क नहीं है और उनके 2जी ग्राहकों का एआरपीयू उचित है क्योंकि वे वॉइस के लिए भुगतान करते हैं जबकि 4जी में वॉइस सेवा मुफ्त दिखती है।

नजर 2जी ग्राहकों पर

- जियो को इससे अधिक से अधिक 2जी ग्राहकों को 4जी में लाने में मदद मिलेगी
- भारती एयरटेल के कुल करीब 28.30 करोड़ ग्राहकों में 4जी ग्राहकों की संख्या 7.7 करोड़ है
- वोडाफोन आइडिया के कुल करीब 31.1 करोड़ ग्राहकों में 3जी/4जी ग्राहकों की संख्या 11.22 करोड़ है
- रिलायंस जियो के कुल करीब 37 करोड़ ग्राहकों में सभी 4जी ग्राहक हैं

वोडा-आइडिया, एयरटेल के नुकसान से जियो को फायदा

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 26 फरवरी

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और रिलायंस जियो के मोबाइल ग्राहकों की संख्या बढ़ी है। जबकि शुल्क दरों में वृद्धि के बाद वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल को काफी ग्राहक खोने पड़े हैं।

आंकड़ों से पता चलता है कि बीएसएनएल ने 4,26,958 ग्राहक जोड़े जबकि जियो के वायरलेस नेटवर्क में 82,308 ग्राहकों का इजाफा हुआ। जबकि वोडाफोन आइडिया को 36 लाख ग्राहकों का और एयरटेल को 11,050 ग्राहकों का नुकसान हुआ।

नवंबर में वायरलेस दूरसंचार के ग्राहक आधार को 2.88 करोड़ ग्राहकों का झटका लगा था। इसकी मुख्य वजह वोडाफोन आइडिया रही जिसे 3.64 करोड़ ग्राहकों का नुकसान हुआ था। भारत में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या नवंबर के अंत में करीब 117.59 करोड़ थी जो घटकर दिसंबर के अंत में 117.24 करोड़ रह गई। इस प्रकार मासिक गिरावट दर 0.29 फीसदी रही।

दिसंबर के अंत में ग्रामीण और शहरी टेलीफोन ग्राहकों की हिस्सेदारी क्रमश: 43.50 फीसदी और 56.50 फीसदी रही।

दिसंबर के अंत में शहरी क्षेत्र में वायरलेस ग्राहकों की कुल संख्या को 36.6 ग्राहकों का झटका लगा जबकि ग्रामीण क्षेत्र में वायरलेस सबस्क्रिप्शन में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों ने 3 दिसंबर को विभिन्न प्लान के तहत कीमतों में 40 फीसदी तक का इजाफा किया था। सितंबर 2016 में जियो के इस क्षेत्र में उतरने के तीन साल बाद दूरसंचार कंपनियों द्वारा शुल्क दरों में की गई यह पहली वृद्धि है। उसके कुछ दिनों बाद जियो ने शुल्क दरों में वृद्धि की घोषणा की थी।

ट्राई ने यह आंकड़ा ऐसे समय में जारी किया है जब समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अनुकूल न रहने के कारण दूसरी तिमाही में इन दोनों कंपनियों भारी नुकसान दर्ज किया था।

एयरटेल के पास 5 अरब डॉलर चुकाने की क्षमता : मूडीज

भाषा
नई दिल्ली, 26 फरवरी

मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने कहा है कि निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल के पास 5 अरब डॉलर के सांविधिक बकाया चुकाने की क्षमता है। उच्चतम न्यायालय ने इसी महीने दूरसंचार कंपनियों से कहा था कि वे उसके 24 अक्टूबर, 2019 के फैसले का अनुपालन करें। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में दूरसंचार विभाग की एजीआर की परिभाषा को उचित ठहराया था।

मूडीज ने बुधवार को कहा कि भारती एयरटेल पर एजीआर के पिछले बकाया की देनदारी 35,300 करोड़ रुपये या 5 अरब डॉलर की है। हालांकि, दूरसंचार कंपनी इसका अंतिम आंकड़ा निकालने के लिए स्व-आकलन कर रही है। मूडीज ने कहा कि 35,300 करोड़ रुपये के नकद भुगतान से भारती एयरटेल की ऋण की गुणवत्ता पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कंपनी को मूल राशि और ब्याज मिलाकर 25,200 करोड़ रुपये का ही भुगतान करना पड़ता है तो मौजूदा रेटिंग में उसकी स्थिति संतोषजनक रहेगी।

नई लैंड रोवर डिफेंडर की बुकिंग शुरू

जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) ने भारत में अपनी नई लैंड रोवर डिफेंडर की बुकिंग शुरू कर दी है। इस मॉडल में 300 पीएस पेट्रोल पावरट्रेन लगी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 69.99 लाख रुपये से शुरू होगी। यह वाहन दो श्रेणियों- तीन दरवाजे के संस्करण (90) और पांच दरवाजे के मॉडल (110) में उपलब्ध होगा। जगुआर लैंड रोवर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित सूरी ने बयान में कहा कि नई डिफेंडर में 21वीं सदी का आधुनिक पैकेज है। नई डिफेंडर 90 और 110 पांच संस्करणों- बेस, एस, एसई, एचएसई और फर्स्ट एडिशन में उपलब्ध होगी। *भाषा*

बीएस बातचीत

'सूचीबद्ध होने की हमारी कोई योजना नहीं'

जीवन बीमा क्षेत्र में इस साल अच्छी रफ्तार के साथ वृद्धि दर्ज की है लेकिन अर्थव्यवस्था में मंदी के खिंचने से वृद्धि को लेकर अनिश्चितता का माहौल दिख रहा है। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी **तरुण चुघ** ने **सुब्रत पांडा** से बातचीत में कंपनी की योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। पेश हैं मुख्य अंश:

क्या आर्थिक मंदी के कारण बीमा क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?
अभी नहीं। इस साल जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा है और लोग जीवन बीमा के लिए बचत कर रहे हैं। इसने 17 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है और इस क्षेत्र के लिए लगातार दमदार प्रदर्शन कर रहा है। हमने उद्योग के औसत कहीं अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कब तक जारी रहेगा क्योंकि अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है।

कंपनी जीवन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करती रही है। अब तक उसका क्या नतीजा दिखा?
उसका प्रदर्शन दमदार है लेकिन मुझे लगता है कि यह धारा 80सी के खिलाफ एक बचाव होगा। बीमा नियामक ने 1 फरवरी से आवश्यकता विश्लेषण पर जोर दिया है। जहां तक हमारा सवाल है तो हमारे पास इसका खाका पहले से ही तैयार था। कंपनी की सोच और प्रस्तुति खुद ग्राहकों के जीवन लक्ष्यों पर केंद्रित है। बीमा नियामक का कहना है कि हरेक पॉलिसी आवश्यकता विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए और इससे हमें खाइयों को पाटने में मदद मिली है। इससे पहले हम जीवन के उद्देश्य और संपत्ति सृजन पर ध्यान देते थे लेकिन अब हम टर्म इंश्योरेंस के लिए जीवन के स्पष्ट उद्देश्य पर जोर देते हैं।

बीमा नियामक ने कहा है कि एक निश्चित आकार तक पहुंचने वाली बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध हो जाना चाहिए। क्या आपकी कंपनी आईपीओ लाने की योजना बना रही है?
फिलहाल हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। लेकिन जहां तक बहीखाते का सवाल है तो हम किसी सूचीबद्ध कंपनी के मुकाबले कहीं अधिक खुलासा कर रहे हैं। सूचीबद्ध होने का पूरा लाभ तभी मिलता है जब आपको रकम की जरूरत हो अथवा प्रशासन संबंधी मुद्दे पर शेयरधारकों का कोई व्यापक हित हो। हमेशा से हम सभी तरह के खुलासे करते रहे हैं।

वितरण के मोर्चे पर ऑनलाइन चैनल का प्रदर्शन कैसा है?
हमारे लिए ऑनलाइन का योगदान करीब 10 फीसदी है और हमारा ग्राहक आधार काफी हद तक स्नातकों और मिलेनियल युवाओं का है। यह काफी हद तक जीवन के उद्देश्य पर आधारित है और उसका दायरा मुख्य तौर पर बड़े शहरों तक सीमित है। काफी ग्राहक मोबाइल के जरिये आते हैं।

टोयोटा किर्लोस्कर ने उतारी पहली लक्जरी एमपीवी

बीएस संवाददाता
हैदराबाद, 26 फरवरी

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (केटीएम) ने आज टोयोटा की ग्लोबल एमपीवी (मिनी वैन) न्यू वेलफायर भारत में उतार दी, जिसकी कीमत 79.5 लाख रुपये है। वैश्विक स्तर पर इसके छह लाख वाहन बिक चुके हैं और सेल्फ चार्जिंग इलेक्ट्रिक वाहन केटीएम की पहली लक्जरी पेशकश है। कुछ समय बाद ऐसे एक या दो वाहन और उतारे जा सकते हैं।

कंपनी ने कहा कि पहले तीन खेप में आने वाले 180 वाहन बिक चुके हैं और नए खरीदारों को अप्रैल से डिलिवरी का इंतजार करना होगा। कंपनी ने वेलफायर को मजबूत हाइब्रिड वाहन करार दिया, जो 40 फीसदी दूरी और 60 फीसदी समय इलेक्ट्रिक पर चलने में सक्षम है। हाइब्रिड मोबिलिटी टेक्नोलॉजी के लिए यह अहम है क्योंकि यह परंपरागत व शुद्ध रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों के मुकाबले पर्यावरण के अनुकूल सबसे अच्छा विकल्प है। केटीएम के वाइस चेयरमैन विक्रम किर्लोस्कर ने कहा, कंपनी का इरादा कम कार्बन उत्सर्जन के हक में व्यावहारिक बदलाव लाने का है।

कंपनी के मुताबिक, 2.5 लीटर गैसोलीन हाइब्रिड इंजन व दोहरे मोटर से लैस नई वेलफायर हाइब्रिड एक लीटर में 16.35 किलोमीटर का माइलेज देती है। पिछले साल भारत में लक्जरी कार निर्माताओं ने उतारचढ़ाव का सामना किया, लेकिन कंपनी का मानना है कि वेलफायर उन्हें आकर्षित करेगी जो इस कीमत दायरे में वाहन के लिए भुगतान करने के इच्छुक हैं।

केटीएम के प्रबंध निदेशक मासाकाजू योशिमूरा ने कहा, पर्यावरण के अनुकूल वाहन अपनाने में तेजी मिश्रित ऊर्जा वाली तकनीक मसलन हाइब्रिड के इस्तेमाल से आएगी, न कि शुद्ध रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों से।

डेमलर इंडिया की नजर रक्षा और एलसीवी खंड पर

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 26 फरवरी

जर्मनी की दिग्गज वाहन कंपनी डेमलर की भारतीय शाखा डेमलर इंडिया कॉमर्शियल व्हीकल (डीआईसीवी) घरेलू वाणिज्यिक वाहन उद्योग में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा वाहनों, ऑफ-हाइवे इंजनों और हल्के वाणिज्यिक वाहन (एलसीवी) आदि जैसे नए क्षेत्र तलाश रही है। डीआईसीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी सत्यकाम आर्य ने कहा कि ट्रकों के अलावा कंपनी नवोन्मेष संस्कृति, कारोबार के नए विचारों और राजस्व प्रवाह को बढ़ावा देना चाहती है।

एक तरफ कंपनी रक्षा, ऑफ-हाइवे इंजन विनिर्माण और एलसीवी आदि से संबंधित क्षेत्र में उद्यमशीलता तलाश रही है, वहीं दूसरी ओर कंपनी का कहना है कि वह नवोन्मेष के लिए शिक्षा संस्थानों और माल ढुलाई करने वाले एग्रीगेटर्स के साथ सहयोग, परामर्श और धन देने के लिए तैयार है। आर्य ने कहा कि विविधीकरण भी राजस्व बढ़ाने और कंपनी की जोखिम से बचने की रणनीति का हिस्सा है।

वर्ष 2019 में डीआईसीवी ने लगभग 6,300 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो वर्ष 2018 के राजस्व की तुलना में 10-12 प्रतिशत अधिक है। रक्षा क्षेत्र में पैठ के बारे में उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार की नीति रक्षा के उद्देश्य से आपूर्ति करने के लिए विदेशी कंपनियों की मदद नहीं करती हैं, लेकिन हाल ही में सरकार ने इस संकेत दिया है कि वह डैमिलेर जैसे कंपनियों की भागीदारी के लिए अप्रैल तक नीति में राहत दे सकती है। वर्तमान में इस खंड में टाटा, अशोक लीलैंड और महिंद्रा समेत भारतीय कंपनियों का वर्चस्व है।

रक्षा खंड के लिए डीआईसीवी 4×4 ट्रकों के विकास पर विचार कर रही है। आर्य ने कहा कि कंपनी हल्के या छोटे वाणिज्यिक वाहनों पर विचार करेगी। फिलहाल भारत में नौ टन से कम वाले खंड में करीब 5,00,000 वाहनों की क्षमता है और इसमें नई कंपनियों के लिए काफी गुंजाइश है। अगर कोई नई कंपनी इस खंड में प्रवेश करना चाहती है तो इलेक्ट्रिक उत्पाद के साथ इसमें प्रवेश करना सही रणनीति होगी और डीआईसीवी इस अवसर पर विचार करेगी।

डीआईसीवी ने कैलेंडर वर्ष 2019 का समापन भारत में 14,500 भारतबेंज की थोक बिक्री के साथ किया है, जबकि वर्ष 2018 में यह संख्या 22,500 थी। इस तरह इसमें 36 प्रतिशत की गिरावट आई है।

अपोलो टायर्स में निवेश करेगी वारबर्ग पिनकस

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 26 फरवरी

प्राइवेट इक्विटी फर्म वारबर्ग पिनकस, अपोलो टायर्स लिमिटेड में 15 करोड़ डॉलर यानी करीब 1,080 करोड़ रुपये निवेश करेगी। बाजार सूत्रों ने कहा कि यह निवेश कंपनी की करीब 20 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर बैठता है।

अपोलो टायर्स के निदेशक मंडल ने आज एमराल्ड सेज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 10.8 करोड़ अनिवार्य परिवर्तनीय तरजीही शेयर जारी करने को मंजूरी दी। कंपनी ने एक्सचेंज को भेजी सूचना में यह जानकारी दी। एमराल्ड सेज, अमेरिका की वारबर्ग से संबद्ध कंपनी है। सूत्रों ने कहा कि तरजीही शेयर को परिवर्तित करने पर यह कंपनी की 20 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर होगी। उल्लेखनीय है कि वारबर्ग के पास पहले से ही कंपनी की 9 फीसदी हिस्सेदारी है।

कंपनी ने हालांकि इस बारे में और जानकारी देने से इनकार कर दिया। कंपनी ने कहा, इस रकम का इस्तेमाल कंपनी के सामान्य कामकाज पर होगा।

यह रकम ऐसे समय में जुटाई जा रही है जब अपोलो भविष्य में

देसी व निर्यात बाजारों की मांग पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता पर निवेश कर रही है। 2019-20 के लिए अनुमानित पूंजीगत खर्च 2,400 करोड़ रुपये है जबकि 2020-21 के लिए कंपनी ने 1,400-1,500 करोड़ रुपये के खर्च का खाका खींचा है।

अपोलो टायर्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक ओंकार एस कंवर ने कहा, कंपनी में वारबर्ग पिनकस का निवेश हमारे कारोबार, प्रबंधन टीम और बढ़त की संभावना में मजबूत भरोसा बताता है।

वारबर्ग पिनकस इंडिया के प्रबंध निदेशक व प्रमुख विशाल महादेविया ने कहा, हम अपोलो टायर्स में अच्छी बढ़त देख रहे हैं। इस यात्रा में अपोलो की प्रबंधन टीम के साथ साझेदारी पर वारबर्ग पिनकस उत्साहित है।

इंडसइंड बैंक के प्रमुख की दौड़ में टाटा कैपिटल के सबरवाल

रघु मोहन
मुंबई, 26 फरवरी

इंडसइंड बैंक के रमेश सोबती के उत्तराधिकारी की दौड़ थोड़ी दिलचस्प हो गई है क्योंकि टाटा कैपिटल के राजीव सबरवाल भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं।

अब टाटा कैपिटल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी सबरवाल और हिंदुजा के प्रवर्तित बैंक के मौजूदा प्रमुख (उपभोक्ता कर्ज) सुमंत कठपालिया के बीच यह दौड़ दोतरफा हो गई है। साथ ही यह पहला मौका है जब किसी एनबीएफसी के प्रमुख को बैंक के संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है। इंडसइंड बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ सोबती का कार्यकाल इस साल 23 मार्च को खत्म हो रहा है।

निजी क्षेत्र के दो बैंकों में बाहरी लोग सत्ता संभाल चुके हैं - एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अमिताभ चौधरी ने ऐक्सिस बैंक में शिखा शर्मा की जगह ली है जबकि डॉयचे बैंक के रवनीत गिल ने येस बैंक से राणा कपूर के निकलने के बाद पद संभाला। चंदा कोछड़ के बाद पद संभालने वाले संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के मुख्य परिचालन अधिकारी थे और तीन दशक से आईसीआईसीआई समूह के दिग्गज रहे हैं।

इंडसइंड बैंक के साथ कोई मसला नहीं जुड़ा है, जो उसके उत्तराधिकार की दौड़ को अलग बनाती है, जैसा कि आईसीआईसीआई बैंक, ऐक्सिस बैंक और येस बैंक के मामलों मे देखा गया था। यह हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि आरबीआई शायद अनिवार्य रूप से किसी आंतरिक व्यक्ति को बने रहने पर जोर नहीं दे सकता है। देश के किसी अन्य बैंक में सभी आला अधिकारी अपने कैरियर के ज्यादातर समय प्रमुख के तौर पर बैंक के साथ जुड़े नहीं रहे हैं। हमेशा ही कयास लगाए गए थे कि अगर किसी एक को सोबती की जगह तैनात किया गया तो पूरी टीम एकसाथ रह पाएगी, यह निश्चित नहीं है। यह चिंता साल 2014 में विश्लेषकों ने जताई थी जब उनके कार्यकाल में एक साल की बढ़ोतरी की गई थी। वह 2015 में 65 साल के हो गए, जो तब निजी बैंक के प्रमुख के अवकाश प्राप्त करने की सीमा थी। एक साल का विस्तार तब कंपनी अधिनियम के तहत दिया गया था और उसकी सीमा 70 साल की गई थी। सबरवाल का नाम आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मौजूदा अग्रणी टीम वहां एक साथ रह पाएगी।

अगर आरबीआई सबरवाल के नाम को हरी झंडी देता है तो एचडीएफसी बैंक में भी बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है जहां प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी का कार्यकाल 26 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो रहा है। माना जा र हा है कि दोनों बैंक के मौजूदा प्रबंधन की तरफ से चुने गए उम्मीदवार को जरूरी नहीं है कि केंद्रीय बैंक की मंजूरी मिल ही जाए। केंद्रीय बैंक उम्मीद करता है कि निजी बैंक उत्तराधिकार की योजना अग्रिम तौर पर बनाए ताकि आंतरिक या बाहरी उम्मीदवार के चयन के लिए पर्याप्त समय हो।

कौन होगा सोबती का उत्तराधिकारी

- टाटा कैपिटल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी सबरवाल और हिंदुजा के प्रवर्तित बैंक के मौजूदा प्रमुख (उपभोक्ता कर्ज) सुमंत कठपालिया के बीच यह दौड़ दोतरफा हो गई है
- यह पहला मौका है जब किसी एनबीएफसी के प्रमुख को संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा है
- निजी क्षेत्र के दो बैंकों में बाहरी लोग सत्ता संभाल चुके हैं - एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के अमिताभ चौधरी ने ऐक्सिस बैंक में जबकि डॉयचे बैंक के रवनीत गिल ने येस बैंक में पद संभाला

अंकेक्षण के नए नियम फर्मों को धोखाधड़ी से बचाएंगे

रुचिका चित्रवंशी
नई दिल्ली, 26 फरवरी

अंकेक्षक समुदाय के बीच वित्तीय अनुशासन लाने के लिए सरकार ने अंकेक्षकों से कहा है कि वे कंपनी की तरफ से दिए गए हर तरह के कर्ज की विस्तृत जानकारी मुहैया कराए, चाहे वह व्हिसलब्लोअर की शिकायतों पर आधारित हो या अंकेक्षण की आंतरिक व्यवस्था के आधार पर।

कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कंपनीज अडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2020 अधिसूचित कर दिया है, जो अंकेक्षकों की तरफ से जांच-परख (ड्यू डिलिजेंस) और डिस्क्लोजर में इजाफे के लिए है। साथ ही कंपनी की पारदर्शी वित्तीय स्थिति ऐसे समय में सामने रखने की बात है जब अंकेक्षक नियामकीय कोप का सामना कर रहे हैं। यह नियम 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद के वित्त वर्ष के ऑडिट रिपोर्ट पर लागू होगा। इस संशोधन में सूचना साझा करने की ज्यादा जिम्मेदारी कंपनियों पर डाली गई है। चूंकि अंकेक्षण का प्रोफेशन जांच के घेरे में है और चार बड़ी कंपनियों से दो ऑडिट क्लाइंटों के लिए गैर-ऑडिट सेवाएं बंद कर रही है। अंकेक्षकों को अब रिपोर्टिंग के सख्त मानकों का इस्तेमाल करना होगा।

अंकेक्षण की गुंजाइश अपनी मौजूदा सीमा से बाहर करने के लिए अंकेक्षकों को अब यह खास तौर से पुनर्भुगतान की किसी शर्तों के बिना लिए गए कर्ज, कुल कर्ज का प्रतिशत और प्रवर्तकों व संबंधित पक्षकारों को दिए गए कर्ज के बारे में जानकारी देनी होगी।

कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स के पार्टनर अंकित सिंघी ने कहा, सरकार ने कंपनियों की तरफ से निवेशकों व नियामकों को भ्रमित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खामियों को रोकने के लिए धोखाधड़ी वाले घटनाक्रम से सबक लिया है।

कंपनीज अडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर 2016 के उपबंधों को दोबारा तैयार किया गया है ताकि वैसी अचल परिसंपत्तियों की जानकारी मिल जाए, जो कंपनी के नाम पर नहीं है, लेकिन वित्तीय विवरण में उसका खुलासा किया गया है।

बेनामी परिसंपत्ति वाली कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही का खुलासा और क्या कंपनी ने वित्तीय विवरण में इसका खुलासा किया है, उसकी जानकारी भी अंकेक्षक को देनी होगी। आईएलऐंडएफएस जैसे मामलों से संकेत लेते हुए सरकार ने अंकेक्षकों से कहा है कि वे कंपनियों के संबंधित अंकेक्षकों की तरफ से एकीकृत वित्तीय विवरण में शामिल टिप्पणी (प्रतिकूल टिप्पणी) का जिक्र करे। हालांकि पहले के नियम के तहत अंकेक्षकों को कंपनी के प्रवर्तक या अधिकारियों की तरफ से की गई किसी तरह की धोखाधड़ी की रिपोर्ट देनी जरूरी होती थी, लेकिन अंकेक्षक रिपोर्ट में अब इसकी जानकारी देनी होगी।

दमानी परिवार ने ली इंडिया सीमेंट्स की 7.27 फीसदी हिस्सेदारी

गिरीश बाबू
चेन्नई, 26 फरवरी

भारत के अमीर परिवारों में से एक दमानी परिवार ने इंडिया सीमेंट्स में अपनी हिस्सेदारी 7.27 फीसदी बढ़ाकर 11.98 फीसदी कर ली है। दमानी फैमिली ने खुले बाजार से शेयर खरीदे। इंडिया सीमेंट्स का शेयर बुधवार को 20 फीसदी उछल गया और इस तरह से दमानी परिवार की तरफ से शेयर खरीद के बाद दो दिन की बढ़त 40 फीसदी से ज्यादा हो गई।

एनएसई की ब्लॉक डील की सूची के मुताबिक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स के संस्थापक राधाकृष्ण दमानी और गोपालकृष्ण दमानी ने 11.1 करोड़ शेयर 111 करोड़ रुपये में खरीदे।

बीएसई के मुताबिक गोपालकृष्ण दमानी, राधाकृष्ण दमानी, श्रीकांतिदेवी दमानी और डिराइव इन्वेस्टमेंट्स ने कुल 2.25 करोड़ शेयर खरीदे। गोपालकृष्ण व राधाकृष्ण डिराइव इन्वेस्टमेंट्स में साझेदार हैं। बुधवार को इंडिया सीमेंट्स का शेयर 19.95 फीसदी उछलकर 104.60 रुपये पर बंद हुआ। फोर्ब्स रियल-टाइम अरबपतियों की सूची में दमानी परिवार को मुकेश अंबानी को बाद दूसरा स्थान मिला है और उनकी हैसियत 17.3 अरब डॉलर है। राधाकृष्ण दमानी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के संस्थापक हैं, जो डीमार्ट खुदरा शृंखला का परिचालन करती है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की फरवरी 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के नतीजे में दक्षिण भारत में मांग में सुस्ती को रेखांकित किया गया है और वहां वॉल्यूम 10 फीसदी घटा है। दक्षिण भारत में मांग में सुधार और कीमत में इजाफे पर नजर रहेगी।

रिटेल 2.0: डेटा, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर जोर

विवेट सुजन पिंटो
मुंबई, 26 फरवरी

भारतीय खुदरा क्षेत्र के लिए 2020 का दशक काफी बदलाव वाला रहा है क्योंकि इस दौरान बाजार में नए प्रतिस्पर्धी, ताकत और चुनौतियां उभरकर सामने आईं। हालांकि पिछले 10 वर्षों के दौरान ई-कॉमर्स में काफी वृद्धि दिखी है और इस क्षेत्र को पूंजी संपन्न विदेशी एवं भारतीय कंपनियों द्वारा काफी उथल-पुथल का सामना करना पड़ा लेकिन सुविधा, समीप और उधारी के कारण ग्राहकों के लिए छोटे किराना स्टोरों की प्रासंगिकता लगातार बनी रही।

हालांकि मुंबई में आयोजित रिटेल लीडरशिप समिट के दौरान रिटेलरों और विशेषज्ञों ने कहा कि मौजूदा दशक में सीमाएं काफी धूमिल हुई हैं क्योंकि नए खिलाड़ी मैदान में आ रहे हैं जबकि मौजूदा कंपनियां अग्रणी बरकरार रहने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के प्रबंध निदेशक एवं वरिष्ठ पार्टनर अभीक सिंघी ने कहा, 'उदाहरण के लिए सोशल कॉमर्स एक नए प्रतिस्पर्धी के तौर पर सामने आया है जो आगामी वर्षों में अपना दायरा बढ़ा सकता है।' उन्होंने कहा, 'उद्योगों के बीच आपसी व्यापार बढ़ सकता है जहां कंपनियां विस्तारित पेशकश और कारोबारी मॉडल के जरिये खुदरा बाजार में दस्तक दे सकती हैं।' इसलिए खुदरा कंपनियों के लिए रणनीति डेटा, प्रौद्योगिकी और नवाचार का अधिक से अधिक फायदा उठाने की होनी चाहिए।

डेलॉयट के पार्टनर (परामर्श) आनंद रामनाथन ने कहा, 'खुदरा विक्रेता एक गतिशील माहौल में कारोबार करते हैं जहां हर समय बदलाव हो रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जैसी ऐसेट-लाइट डिजिटल प्रौद्योगिकी की तैनाती के जरिये खुदरा विक्रेता औसत बिल मूल्य, वर्गीकरण योजना और ब्रांड अनुभव में सुधार कर सकता है जिससे आउटलेट में बिक्री को रफ्तार मिल सके।'

विश्लेषकों ने कहा कि तगड़ी प्रतिस्पर्धा, अधिक लोगों की जरूरत, रियल एस्टेट एवं अन्य लागत के कारण रिटेलरों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में उनका जोर हल्की आपूर्ति-शृंखला वाले मॉडल, बाजार में तेजी से प्रसार एवं उपयुक्त योजना और मांग के अनुरूप आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बीच, मैकडॉनल्ड्स और पिज्जा हट जैसी कुछ क्विक-सर्विस रेस्टोरेंट शृंखला अपने स्टोरों में डिजिटलीकरण को पहले से ही बढ़ावा दे रही हैं।

2,000 करोड़ रु. राजस्व का एचऐंडएम का लक्ष्य

विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फैशन रिटेलर हाइंज ऐंड मॉरिट्ज (एचऐंडएम) इंडिया के प्रमुख जेनी इनोला ने कहा है कि भारत में 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व करोड़ रुपये का राजस्व हासिल करने का कंपनी का लक्ष्य है। यह बाजार तेजी गति से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है।

वैश्विक स्तर पर इंडिटेक्स की ज़ारा (दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फैशन कंपनी) के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली रिटेलर यह लक्ष्य कैलेंडर वर्ष के आखिर तक हासिल कर सकती है। भारतीय प्रमुख ने कहा कि ऑनलाइन व ऑफलाइन बिक्री, स्थानीय सहयोग और अफोर्डेबल मर्केंडाइज के दम पर यह लक्ष्य हासिल हो जाएगा। एचऐंडएम दिसंबर से नवंबर को लेखा वर्ष मानती है। भारत में उसके 47 स्टोर हैं।

खुदरा विशेषज्ञों ने कहा, ऐसे में एचऐंडएम की बिक्री की रफ्तार साल 2020 में 40 फीसदी से ज्यादा बनी रहेगी और यह ऐसे समय में होगा जब देसी उपभोग में मंदी है। *बीएस*

बंधन बैंक की शाखाओं के विस्तार की तैयारी

नम्रता आचार्य
कोलकाता, 26 फरवरी

शाखाएं खोलने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक से राहत मिलने के बाद बंधन बैंक ने अगले एक महीने में 250 बैंकिंग आउटलेट (डोरस्टेप बैंकिंग सेंटर सहित) खोलने पर विचार कर रहा है। बैंक के लिए यह छूट बड़ी राहत बनकर आई है। बंधन बैंक पर प्रमोटरों की होल्डिंग 40 प्रतिशत होने के नियामकीय मानक पूरा न करने के कारण जुर्माने के रूप में शाखाओं के विस्तार पर रोक लगा दी गई थी। बंधन बैंक के सीईओ और एमडी सीएस घोष ने कहा, 'इस पत्र के माध्यम से नियामक ने अब बैंक की पहचान अनुपालन करने वाले बैंक के रूप में की है। यह एक संकेत हमें दिया गया है। इससे बैंक को ताकत मिली है।' उन्होंने कहा, 'हम मार्च 2020 के अंत तक 250 और बैंकिंग आउटलेट जोड़ेंगे।' इस समय बैंक का 1,100 शाखाओं और 3084 डोरस्टेप बैंकिंग सेंटर का नेटवर्क है। मार्च 2019 और दिसंबर 2019 के बीच बैंक ने 23 शाखाएं और 70 डीएससी खोले हैं। इसके साथ ही गृह फाइनैंस के विलय के साथ 195 और शाखाएं जुड़ी थीं। रिजर्व बैंक ने 2018 में उसकी मंजूरी के बगैर नई शाखाएं खोलने को लेकर बंधन बैंक पर प्रतिबंध लगा दिया था और बैंक को आदेश दिया था कि शेयरहोल्डिंग नियमों का पालन न करने के कारण घोष का वेतन मौजूदा स्तर पर स्थिर रखा जाए। कुछ महीने पहले बैंक ने गृह फाइनैंस के विलय की प्रक्रिया पूरी की है, जिसकी वजह से प्रवर्तकों की हिस्सेदारी 61 प्रतिशत रह गई।

नीरव मोदी की 112 वस्तुओं की नीलामी होगी

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की हीरे की महंगी घड़ियों, कार और दुर्लभ कलाकृतियों समेत 112 सामानों की नीलामी गुरुवार को होगी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सैफरनआर्ट इस नीलामी को अंजाम देगी। इसके बाद 72 सामानों की अगले सप्ताह ऑनलाइन नीलामी तीन और चार मार्च को हो सकती है। नीरव मोदी पर पंजाब नैशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी का आरोप है। वह देश से फरार हैं और इस समय लंदन की एक जेल में हैं। सैफरनआर्ट ने मोदी की कुछ कलाकृतियों की पिछले साल नीलामी की थी। *भाषा*

जीडीपी वृद्धि रह सकती है 5 फीसदी से नीचे

अभिषेक वाघमारे
नई दिल्ली, 26 फरवरी

अर्थव्यवस्था में गिरावट की स्थिति में हाल फिलहाल में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं नजर आ रही हैष अर्थशास्त्रियों का मानना है कि दिसंबर तिमाही के वृद्धि के आंकड़ों में शिथिलता जारी रहेगी। बिजनेस स्टैंटर्ट के सर्वे में शामिल किसी अर्थशास्त्री ने यह नहीं कहा कि वित्त वर्ष 20 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 5 प्रतिशत से ज्यादा रहेगी।

वहीं अर्थशास्त्रियों का यह भी कहना है कि कुछ संकेतक ऐसे हैं, जो बेहतरीन वृद्धि के संकेत दे रहे हैं और तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर दूसरी तिमाही की तुलना में ज्यादा रह सकती है। साथ ही कोई भी यह उम्मीद नहीं कर रहा है कि पूरे साल की वृद्धि दर 5 प्रतिशत से ऊपर जाएगी।

शुक्रवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय तीसरी तिमाही के जीडीपी के आंकड़े और चल रहे वित्त वर्ष का दूसरा सालाना जीडीपी का अग्रिम अनुमान जारी करेगा।

भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि 33 आर्थिक संकेतकों में से केवल एक चौथाई दिसंबर तिमाही में तेजी के संकेत दे रहे हैं और दूसरी तिमाही जैसी स्थिति है। इसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017-18 की मार्च मिताही में करीब तीन चौथाई संकेतकों ने सकारात्मक वृद्धि दिखाई थी। इसके परिणामस्वरूप एसबीआई ने तीसरी तिमाही की वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जैसा दूसरी तिमाही में था, और यह 26 तिमाही के न्यूनतम स्तर पर बना रहेगा। इक्रा में मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नैयर ने कहा कि तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि की मामूली सुधार में सरकार की ओर से किया गया व्यय अहम रहेगा। उन्होंने एक नोट में कहा, 'कच्चे माल की लागत सरकार के गैर ब्याज राजव्य व्यय, कुछ बैंकों की स्थिर कमाई आर्थिक वृद्धि की जमीन तैयार करेगी।'

कृषि, विनिर्माण और सेवा सहित 7 संकेतकों पर नजर डालने से पता चलता है कि कम से कम इनमें से आधे के प्रदर्शन में पहले की तिमाही की तुलना में सुधार है। इससे संकेत मिलते हैं कि वृद्धि दर 4.5 प्रतिशत से थोड़ा ज्यादा रह सकती है। जहां औद्योगिक उत्पादन, रेलवे यात्री और मालभाड़े से कमाई और बिजली की खपत कम हुई है, कृषि क्षेत्र में उत्पादन में बहुत तेजी नजर आई है। डीजल और पेट्रोल की खपत में मामूली सुधार है और हवाई किराये में बढ़ोतरी हुई है। नैशनल सेंटर फॉर अप्लायड इकोनॉमिक रिसर्च ने इसी तरह की स्थिति बताते हुए अपने नोट में कहा है कि जहां कृषि क्षेत्र में तेजी नजर आ रही है, कारोबार और पर्यटकों के आवक के संकेतक सेवा क्षेत्र में कुछ तेजी के संकेत दे रहे हैं। थिंक टैंक को उम्मीद है कि तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 2018 की दिसंबर तिमाही से 4.9 प्रतिशत ज्यादा रह सकती है।

केयर रेटिंग ने कहा है कि वित्तीय सेवा, रियल एस्टेट तीसरी तिमाही में वृद्धि को गति दे सकते हैं, लेकिन यह यह निवेश मांग बढ़ाने और विनिर्माण पर असर डालने के लिए पर्याप्त नहीं है। केयर रेटिंग ने अनुमान लगाया है कि कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर तीसरी तिमाही में 3.3 प्रतिशत रहेगी, जिससे इस तिमाही में 4.5 प्रतिशत वृद्धि दर बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने कोविड 19 के असर को लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि पर पड़ने वाले इसके असर का अनुमान लगाना अभी कठिन है।

कुछ संकेतक दे रहे बेहतर संकेत

मानक	दूसरी तिमाही*	तीसरी तिमाही*
औद्योगिक उत्पादन	-0.4	-0.8
रेल कमाई (करोड़ रु.)	-0.3	-7.7
बिजली की मांग (यूनिट)	1.1	-7.1
कृषि बुआई (हेक्टेयर में)	-0.5	35.5
कृषि उत्पादन (टन में)	0.6	4.1
ईंधन खपत (टन में)	2	2
हवाई यातायात (यात्री)	2.2	5.8

*वित्त वर्ष 2020 में, सालाना वृद्धि दर प्रतिशत में
-खरीफ का उत्पादन दूसरी तिमाही का, रबी का अनुमान तीसरी तिमाही का
स्रोतः रिजर्व बैंक, डीजीसीए, रेलवे बोर्ड, कृषि विभाग, पीपीएसी, नैशनल लोड डिस्पैच सेंटर

आर्थिक नरमी अब समाप्ति की ओर

भारत में आर्थिक सुस्ती अब समाप्ति की ओर है और देश को 10 प्रतिशत वृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए नीतियों को और अधिक खुला बनाने की आवश्यकता है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पानगढ़िया ने यह कहा है। केंद्रीय बजट 2020 पर परिचर्चा के दौरान अपने मुख्य संबोधन में उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। इसके बाद यह 7 से 8 प्रतिशत की दर पर पहुंच जाएगी जैसा की पिछले 15 से 16 साल की अवधि में यह रही है।

भारत के महावाणिज्य दूत द्वारा मंगलवार को भारत-अमेरिका रणनीतिक भागीदारी मंच (यूएसआईएसपीएफ) के साथ भागीदारी में आयोजित इस कार्यक्रम में पानगढ़िया ने कहा, 'आर्थिक सुस्ती के मामले में मेरा अपना आकलन है कि अब यह जितनी नीचे आनी थी आ चुकी है।' उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में जो कि 31 मार्च को समाप्त हो रही है, हमें कुछ सुधार दिखाई देगा। बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन यह निश्चित है कि पहली छमाही के मुकाबले दूसरी छमाही बेहतर होगी। *भाषा*

100 फीसदी एफडीआई को अनुमति के लिए बदलाव

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 26 फरवरी

उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने बीमा मध्यस्थता में स्वचालित तरीके से 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति देने के लिए 2017 की समेकित प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति में संशोधन किए हैं।

इसमें बीमा ब्रोकरों, पुनर्बीमा ब्रोकरों, बीमा सलाहकारों, कॉर्पोरेट एजेंटों, थर्ड पार्टी प्रशासकों और सर्वेक्षकों तथा क्षति आकलनकर्ताओं को शामिल किया गया है। इससे पहले बीमा मध्यस्थता के क्षेत्र में स्वचालित रास्ते से 49 फीसदी तक एफडीआई की ही अनुमति थी। जहां तक बीमा कंपनियों का सवाल है तो स्वचालित रास्ते से 49 फीसदी तक की विदेशी निवेश की अनुमति है जो बीमा नियामक की मंजूरी के अधीन है। और बीमा कंपनियों के लिए एफडीआई नियम से पता चलता है कि उसका स्वामित्व और नियंत्रण हमेशा ही स्थानीय भारतीय कंपनियों के हाथों में ही रहता है। बीमा मध्यस्थता के मामले में यदि बहुलांश हिस्सेदारी विदेशी निवेशकों के पास है तो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत वह कंपनी लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित होनी चाहिए।

नियम बदले

नए मास्टर प्लान में आईटी उद्योगों को मिलेगा प्रोत्साहन

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 26 फरवरी

दिल्ली मास्टर प्लान-2041 के तहत राष्ट्रीय राजधानी में आईटी आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इसके साथ ही पर्यावरण हितैषी उद्योग पर भी जोर रहेगा। यह बात दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआइआई) के दिल्ली चैप्टर के सालाना कार्यक्रम में कही।

उपराज्यपाल ने इस कार्यक्रम में उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली मास्टर प्लान-2041 बनाने पर तेजी से काम हो रहा है जिसे सभी हितधारकों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसमें दिल्ली में आईटी और इससे संबद्ध उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि दिल्ली में औद्योगिक विकास को मौका दिया जा सके। ऐसे उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं।

दिल्ली में परंपरागत भूमि उपयोग नियमन से दूरी बनाकर इन नियमों को आसान बनाया जा रहा है। दिल्ली के योजनाबद्ध विकास के लिए जनभागीदारी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल पर भी जोर देने की आवश्यकता है। इस मॉडल में सरकार, भू-स्वामी और उद्योग बराबर के भागीदार होंगे।

उपराज्यपाल बैजल ने कहा दिल्ली में लैंड पूलिंग नीति के तहत 20,000 हैक्टेयर से अधिक जमीन चिह्नित की गई है जिसमें 6,400 से अधिक भू स्वामियों ने रुचि दिखाई है। बैजल ने इस नीति के तहत किफायती आवास निर्माण हेतु उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया।

उपराज्यपाल ने कहा कि डीडीए द्वारा चिह्नित स्थलों पर कलाकारों को कलाकृतियां स्थापित करने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने सीआईआई और उद्यमियों से कलाकारों व स्थानों को चुनने में मदद करने की अपील की।

नए मार्ग से बचेगा वक्त

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 26 फरवरी

भारत और रूस के बीच परिवहन के समय को 50 दिनों से घटाकर 25 दिन पर लाने के लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर) इस साल से अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) का इस्तेमाल शुरू करेगी। इससे परिवहन लागत में भी कम से कम 30 फीसदी की कटौती होने के आसार हैं।

कॉनकॉर के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) वी कल्याण रामा ने कहा, 'तीन महीने के भीतर यहा मार्ग परिचालित हो जाएगा और दोनों देशों के आयातक और निर्यातक इसका इस्तेमाल करने में सक्षम होंगे। दवाओं, लहसून, मसाले और चाय सहित भारत से बहुत सारे सामानों की रूस में भारी मांग रहती है।' कॉनकॉर और रूस की रेलवे कंटेनर परिवहन सहायक इकाई आरजेडडी लॉजिस्टिक्स जेएससी ने मंगलवार की शाम को एक सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के जरिये एक ही इनवॉइस पर भारत और रूस के बीच कार्गो का परिवहन किया जा सकेगा। गत वर्ष इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया था। सेवा समझौते से एक ही इनवॉइस के जरिये दोनों तरफ से कार्गो का परिवहन किया जा सकेगा। आईएनएसटीसी जहाज, रेल और सड़क मार्ग का 7,200 किलोमीटर लंबा एक मल्टीमोडल नेटवर्क है जो भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मीनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप से गुजरता है।

कॉनकॉर अपनाएगा मल्टीमोडल मार्ग

- **रूस की रेलवे शाखा के साथ की साझेदारी**
- **आईएनएसटीसी मार्ग अपनाने से लागत में आएगी 30 फीसदी कमी**
- **परिवहन की मौजूदा लागतः 4,900 डॉलर प्रति टीईयू**
- **नए मार्ग पर लागत 3,400 डॉलर प्रति टीईयू**
- **साल 2018-19 में भारत और रूस के बीच 8.2 अरब डॉलर का व्यापार हुआ**

आरजेडडी के एक अधिकारी ने कहा ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का इस मार्ग पर असर नहीं होगा और इस मार्ग में शामिल देशों की ओर से संबंधित बैंकों और बीमाकर्ताओं की चिंताओं का समाधान किया गया है। आरजेडडी के अधिकारी ने कहा, 'हमने अपने भारतीय ग्राहकों और बैंकरों की चिंताओं का खयाल रखा है। आईएनएसटीसी के जरिये परिवहन का समय परंपरागत मार्ग की तुलना में आधी रह जाएगी।' हालांकि, एक भारतीय अधिकारी ने कहा कि चाबहार बंदरगाह और बांदर अब्बास के रास्ते आएनएसटीसी के मार्ग पर अभी भी लागत और पारगमन संबंधी कुछ मसले हैं।

भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह का परिचालन कर रहा है जो इस गलियारे पर पड़ता है। अनुमानों के मुताबिक परिवहन की जो मौजूदा लागत 4,900 डॉलर प्रति टीईयू बैठ रही है वह नए मार्ग का इस्तेमाल शुरू करने से घटकर 3,400 डॉलर प्रति टीईयू रह जाएगी। भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख सामानों में दवाइयां, कल पुर्जे, ब्यॉलर, जैविक रसायन, कॉफी, चाय और मसाले शामिल हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 10

अनिश्चितता बरकरार

इस सप्ताह यह स्पष्ट हो गया कि चीन के वुहान शहर से उभरा कोरोनावायरस आसानी से नियंत्रण में आने वाला नहीं है। दुनिया भर में इसके पीड़ितों की तादाद में इजाफा देखने को मिला है। कई सप्ताह तक कोरोनावायरस के शुरुआती चिह्न चीन में नजर आए।

वहां भी खासतौर पर हुबेई प्रांत में जहां से यह पैदा हुआ। परंतु गत सप्ताह रोज नए सामने आने वाले मामलों में से 20 फीसदी चीन के बाहर के हैं। यहां तक कि ईरान और इटली में भी कई नए मामले देखे गए। संभव है कि हुबेई प्रांत को अलग-थलग करके बीमारी को नियंत्रित करने की नीति नाकाम हो गई हो। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को यह जानना चाहिए कि जोखिम में बदलाव की संभावना हमेशा से रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि विभिन्न देशों को महामारी की आशंका से निपटने की तैयारी रखनी चाहिए।

तथ्य तो यह है कि ऐसे वैश्विक प्रसार वाले वायरस को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। सन 2002 में सार्स (सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) का प्रसार भी तेजी से हुआ था लेकिन यह सीओवीआईडी-19 से कहीं कम संक्रामक था। दुनिया भी तब उतनी अंतर्संबंधित नहीं थी जितनी कि वह आज है।

सन 2002 में वैश्विक आपूर्ति शृंखला के जोखिम आज जैसे नहीं थे। आज ऑक्सफर्ड इकनॉमिक्स का अनुमान है कि यदि महामारी जैसे हालात बने तो वैश्विक उत्पादन को एक लाख करोड़ डॉलर की क्षति पहुंचेगी। बाजार, खासतौर पर वॉल स्ट्रीट ने ध्यान दिया है कि इन घोषणाओं में जताए जाने वाले अनुमानों में लगातार बदलाव आ रहा है। हर बुरी खबर के साथ अनुमान घटाया जा रहा है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि जोखिम का सही आकलन नहीं किया गया था।

कुछ मायनों में कोरोनावायरस चीन की वरीयता वाले वैश्वीकरण के मौजूदा हालात में तनाव जांचने के औजार की तरह भी है। लागत कम करने के लिए किफायत बढ़ाई गई और यह सुनिश्चित किया गया कि कंपनी के कच्चे माल को हासिल करने की प्रक्रिया की किसी तरह नकल नहीं की जा सके। अभी भी बहुत सीमित अतिरिक्त क्षमता या विकल्प मौजूद है। आपूर्ति शृंखला को स्थानांतरित करने की लागत बहुत अधिक होगी। निश्चित तौर पर यह भी एक वजह है कि चीन में हाल में मेहनताने बढ़ने के बावजूद वैश्विक आपूर्ति शृंखला चीन उस कदर विमुख नहीं हुई जितनी कि अपेक्षा की जा रही थी।

परंतु ऐसी अतिशय निर्भरता हमेशा खतरनाक होती है और असुरक्षा का माहौल बनाती है। सीओवीआईडी-19 वायरस हमें इसी तथ्य की याद दिलाता है। इससे दो सबक निकलते हैं। पहला, चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस तरह अपरिहार्य हो गया है, उसे देखते हुए कई देश कोरोनावायरस के उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकने वाले वास्तविक असर का आकलन करने की दृष्टि से कमजोर तैयारी वाले हैं। भारत में जेनेरिक औषधि समेत कई क्षेत्र कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि यदि भविष्य में समस्या बढ़ती है तो वे अपनी आपूर्ति कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं। इस बीच सरकार ने भी अपनी योजना स्पष्ट नहीं की है। हालांकि वित्त मंत्री ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की लेकिन संभावित प्रतिक्रिया को लेकर कोई बात पारदर्शी ढंग से नहीं कही गई।

यह स्पष्ट नहीं है कि आपूर्ति कब तक बहाल होगी। दूसरा असर चीन की फैक्टरियों पर व्यापक निर्भरता से उपजी समस्या के रूप में सामने है। इसे भी लंबी अवधि के दौरान दूर करना होगा।

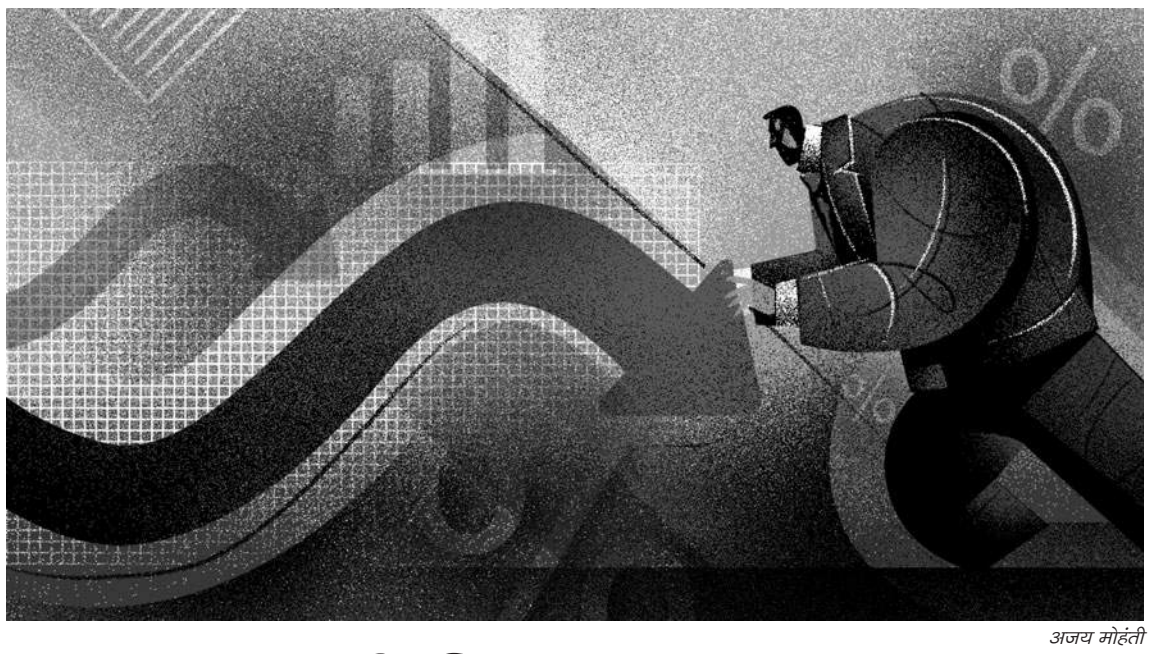

अजय मोहंती

मुद्रास्फीति का लक्ष्य निर्धारण बने प्रभावी

मुद्रास्फीति के लक्ष्य तय करने के लिए मौद्रिक नीति से जुड़ी कुछ समस्याओं का हल जल्द निकालने पर ध्यान देना होगा। मौजूदा आर्थिक स्थिति में इसकी अहमियत बता रहे हैं **अजय शाह**

भारत में मुद्रास्फीति के लक्ष्य-निर्धारण की कहानी नवंबर 2005 से शुरू हुई जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 5.3 फीसदी हो गई थी। आंकड़े बताते हैं कि मुद्रास्फीति नियोजन का अगला दशक लंबे मुद्रास्फीति संकट का था। इसने मौद्रिक नीति रणनीति के साथ ही संसद एवं वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बीच प्रिंसिपल और एजेंट के संबंधों को लेकर भी नए सवाल खड़े हुए।

उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था का दुनिया के साथ काफी हद तक एकीकरण हो चुका था और वित्तीय सघनता भी बढ़ चुकी थी। इसके चलते एक बंद अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की अंतर्दृष्टि काम करना बंद कर चुकी थी। उस पुरानी अंतर्दृष्टि ने ही हमें इस दीर्घकालीन मुद्रास्फीति संकट में धकेला था। हमें मुक्त अर्थव्यवस्था के वृहद-अर्थशास्त्र में नए ज्ञान की जरूरत थी।

लंबे समय तक चले मुद्रास्फीति संकट ने एक एजेंट के तौर पर आरबीआई के चरित्र को लेकर भी सवाल खड़े किए। हरेक सरकारी निकाय का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। बाध्यकारी शक्ति मिलने के एवज में उसे एक हद तक नतीजा भी देना होगा। आरबीआई को नोट छापने का अधिकार संसद में पारित कानून से मिला था। आरबीआई को वजूद में लाने वाले 1934 के अधिनियम में इसे एक अस्थायी उपाय के तौर पर डिजाइन बताया गया था। एक बेहतर एवं अधिक स्थायी व्यवस्था की तलाश करने का वक्त था। जब संसद आरबीआई को नोट छापने की शक्ति देती है तो जवाबदेही के तौर पर आरबीआई संसद को क्या देता है?

मुद्रास्फीति संकट के काफी नुकसान होते हैं। भारत में मुद्रास्फीति की सबसे ज्यादा मार गरीबों पर पड़ती है। वहीं मुद्रास्फीति नेताओं की चिंता का प्रमुख मुद्दा होता है। कोई भी नेता यह नहीं चाहता है कि चुनाव में जाते समय मुद्रास्फीति के मोर्चे पर उसका प्रदर्शन खराब हो।

मुद्रास्फीति को कम एवं टिकाऊ स्तर पर रखना मौद्रिक नीति का काम है। जब आरबीआई नाकाम होता है तो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए कोई भी तरीका अपनाने के लिए जबरदस्त राजनीतिक दबाव होता है। जब मैं 2001 में वित्त मंत्रालय से जुड़ा था तो विमल जालान ने मुझे मुद्रास्फीति के बारे में बड़ी अच्छी सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि मुद्रास्फीति के काबू में रहने पर आप आर्थिक नीति के बारे में सोच सकते हैं लेकिन इसके आठ फीसदी पहुंच जाने पर आपको सबकुछ छोड़कर केवल मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए काम करना पड़ता है।

इस तरह मुद्रास्फीति संकट से तमाम मुश्किलें पैदा होती हैं जिनमें निर्यात या आयात पर पाबंदी लगाना और हटाना या सीमा-शुल्कों में बदलाव करना। ये हस्तक्षेप बाजार अर्थव्यवस्था के कामकाज को बाधित करते हैं। जब मुद्रास्फीति को निचले एवं टिकाऊ स्तर पर रखने में आरबीआई नाकाम रहता है तो हम इस तरह के बाध्यकारी कदम उठाने लगते हैं जो बाजार अर्थव्यवस्था की बुनियाद को ही चोट पहुंचाता है। बेहतर तो यही है कि इस तरह का मुद्रास्फीति संकट पैदा ही न हो।

इनमें से कोई भी सवाल अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर नया नहीं है। सभी देशों को इन्हीं मुश्किलों से दो-चार होना पड़ता है। एक केंद्रीय बैंक को किस तरह जवाबदेह बनाना है? निम्न एवं टिकाऊ मुद्रास्फीति का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए? दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रभावी समाधान एक औपचारिक व्यवस्था बनाने का है जिसमें केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति लक्ष्य हासिल करने के लिए जवाबदेह बनाया जाता है।

इसी स्थिति ने गत 20 फरवरी 2015 को 'मौद्रिक नीति प्रारूप समझौता' को जन्म दिया जिसमें मुद्रास्फीति के लक्ष्य तय करने का दायित्व वित्त मंत्रालय एवं आरबीआई के बीच करार में निहित किया गया। इसके एक साल बाद आरबीआई अधिनियम को संशोधित कर मुद्रास्फीति का लक्ष्य तय करने को आरबीआई का उद्देश्य बना दिया गया। यह उचित ही है कि इस संशोधन के साथ ही 1934 अधिनियम में आरबीआई को अंशकालिक निकाय बताने वाले बिंदु को हटा दिया गया। पहली बार आरबीआई के उद्देश्य में स्पष्टता आई और अब यह महज अस्थायी व्यवस्था नहीं रह गई थी।

नए प्रारूप ने कितने अच्छे ढंग से काम किया है? किसी की भी उम्मीदों से बेहतर रहा है। व्यावहारिक लोग सोचते हैं कि मुद्रास्फीति का संबंध केवल फसलों एवं बारिश से है। यह सोचना एक बेहद बौद्धिक अवधारणा है कि वैध रकम पैदा करने के तरीके का लंबे समय में मुद्रास्फीति पर निर्णायक असर होता है। असल में, उच्च बौद्धिक अवधारणा के मुताबिक फसलों एवं बारिश में हमेशा ही उतार-चढ़ाव रहता है वहीं मौद्रिक नीति प्रारूप समझौता संपन्न हो जाने के बाद मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ गई।

आंकड़ों में एक खामी है। दिसंबर 2019 में मौसमी रूप से समायोजित मुद्रास्फीति को 21.3 फीसदी आंका गया। इसका 12 महीनों तक सालाना मुद्रास्फीति पर असर होगा। लेकिन यह कोई बहुत गंभीर मुद्रास्फीतिकारी समस्या नहीं है: जनवरी 2020 में मौसमी समायोजित मुद्रास्फीति फिर से 3.04 फीसदी पर आ गई। फसलों एवं बारिश वितरण से उतार-चढ़ाव आता है लेकिन यह व्यवस्थागत मुद्रास्फीति नहीं है।

मुख्य में यह एक ऐतिहासिक सुधार था, भारत में वैध रकम के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की दिशा में पहला कदम था। अब ऐसे तीन कमजोर बिंदु हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। पहली समस्या मौद्रिक नीति समिति के संयोजन को लेकर है क्योंकि इसमें अकेले आरबीआई गवर्नर के ही पास नियंत्रण होता है। दूसरी समस्या मौद्रिक नीति के उद्देश्य एवं ऋण प्रबंधन उद्देश्य के बीच तनाव की है। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन को आरबीआई से अलग होने की जरूरत है। तीसरी समस्या मौद्रिक नीति के कमजोर संचरण की है: बॉन्ड बाजार, बैंकिंग एवं पूंजी पर नियंत्रण संबंधी सुधारों की जरूरत है ताकि मौद्रिक नीति समिति के फैसलों को अधिक धारदार बनाया जा सके।

कानून के उस प्रावधान को लेकर भी चर्चा है जो पांच वर्षों के बाद यानी फरवरी 2021 में मुद्रास्फीति निर्धारण प्रारूप की समीक्षा करने की जरूरत बताता है। कानून पर नजर डालने से पता चलता है कि पांच साल में मुद्रास्फीति निर्धारण प्रारूप की समीक्षा करने का कोई प्रावधान नहीं है। उल्लेख केवल लक्ष्य की समीक्षा का है ताकि यह परखा जा सके कि वार्षिक आधार पर मुद्रास्फीति लक्ष्य को चार फीसदी से बदलने की जरूरत है या नहीं। इन तीनों समस्याओं का समाधान तलाश लिए जाने के बाद ही 2 फीसदी मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखना वाजिब होगा।

अर्थव्यवस्था में छाई सुस्ती से निपटने के लिए नरम मौद्रिक नीति और शिथिल राजकोषीय नीति की मांगें उठी हैं। हल्की संस्थागत स्मृति से काफी मदद मिलेगी। हमें मौजूदा आर्थिक नीति की समस्याओं में इजाफा करने वाली मुद्रास्फीति संकट या राजकोषीय संकट की कोई जरूरत नहीं है। मौद्रिक नीति केवल यही काम कर सकती है कि स्थायित्व एवं पूर्वानुमेयता का माहौल बनाया जाए। इससे परिवारों एवं कंपनियों के लिए भविष्य में दूर तक देख पाना और उसके हिसाब से विश्वस्त योजना बना पाना संभव होता है। वैध रकम के संस्थागत प्रावधानों को कमजोर करने से निजी निवेश को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

(लेखक नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी, नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं।)

कारोबारी सुगमता में हुआ सुधार लेकिन बढ़ सकती है असहजता

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

हाल के वर्षों में कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत का प्रदर्शन खासा बेहतर रहा है। विश्व बैंक द्वारा अक्टूबर 2019 में तैयार सूचकांक में भारत को 190 देशों की सूची में 63वें स्थान पर रखा गया था। यानी एक वर्ष में भारत ने 14 स्थानों का सुधार किया था। जबकि इससे पिछले वर्ष उसने 23 स्थानों की प्रगति की थी।

विश्व बैंक ने 2019 की अपनी रिपोर्ट में कहा कि बीते कुछ वर्ष के दौरान किए गए सतत कारोबारी सुधारों ने भारत की मदद की है। उसने कहा कि लगातार तीसरे वर्ष भारत शीर्ष 10 सुधारक देशों में शामिल रहा। सूचकांक में भारत की स्थिति बेहतर करने वाले सुधारों में कारोबार शुरू करने के मानक सहज करना, निर्माण परमिट में बेहतरी, सीमा पार व्यापार सहज बनाना और ऋणशोधन के मामले हल करना शामिल है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ क्षेत्र गंभीर चिंता का विषय हैं। मसलन, अनुबंध प्रवर्तन के मामलों में भारत को 190 देशों में 163वां स्थान दिया गया है जबकि परिसंपत्ति पंजीयन में 153वां। बैंक के अनुसार परिसंपत्ति पंजीयन में औसतन 58 दिन और परिसंपत्ति मूल्य का 8 फीसदी व्यय होता है। यह उच्च आय वाले देशों से बहुत ज्यादा है। इसी तरह देश में निचली अदालत में वाणिज्यिक विवाद का मामला निपटने में 1,445 दिन लगते हैं जो विकसित देशों से करीब तीन गुना है। कारोबारी सुगमता सूचकांक में देश के विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ यह देखना होगा कि क्या देश का मौजूदा आर्थिक नीति के माहौल से आने वाले वर्षों में और सुधार हो सकता है। हाल के दिनों में कुछ परेशान करने वाली घटनाएं घटी हैं जो कारोबारी सुगमता को प्रभावित कर सकती हैं। देश के दूरसंचार सेवा प्रदाता अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। सरकार उनसे और अधिक राजस्व की मांग कर रही है और न्याय व्यवस्था राजस्व दावे पर निर्णय सुनाने के पहले मौजूदा बाजार ढांचे को पहचानने से इनकार कर रही है।

सरकार और दूरसंचार कंपनियों के बीच समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का आकलन कई वर्ष पिछड़ गया है। शुरुआत 2003 में हुई थी जब कंपनियों ने कहा था कि एजीआर में केवल दूरसंचार राजस्व शामिल किया जाना चाहिए जबकि सरकार का कहना था कि एजीआर में दूरसंचार और गैरदूरसंचार दोनों तरह के राजस्व शामिल होने चाहिए। एजीआर का आकलन सरकार को चुकता की जाने वाली लाइसेंस फीस के निर्धारण के लिए होना था। सन 1999 में यह एजीआर का 15 फीसदी थी और 2013 में इसे एजीआर का अधिकतम 8 फीसदी कर दिया गया। शुरुआती दौर में अदालती फैसले दूरसंचार कंपनियों के पक्ष में आए। दूसरे शब्दों में अदालत ने सरकार की उच्चतर एजीआर की मांग ठुकरा दी। उस वक्त तक कंपनियों ने दावे का 80 फीसदी चुका दिया था। सरकार ने राशि रिफंड करने के बजाय अपील में न केवल समूची राशि बल्कि ब्याज और जुर्माने की भी मांग की। अपील की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय ने की और सरकार जीत गई। अधिवक्ताओं संजय हेगड़े और प्रांजल किशोर ने बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित एक आलेख में दलील दी थी कि दूरसंचार कंपनियों से मूलधन के अलावा ब्याज और जुर्माना चुकाने को कहना गलत है क्योंकि निचली अदालत में वे जीत गई थीं। यदि सरकार ने ब्याज और जुर्माने पर जोर नहीं दिया होता तो सबसे बड़ी अदालत के निर्णय पर कंपनियों की प्रतिक्रिया अलग होती।

दूरसंचार कंपनियों से की जा रही 1.3 लाख करोड़ रुपये की कुल मांग का बमुश्किल एक-चौथाई हिस्सा मूल धन है, शेष राशि ब्याज और जुर्माने की है। ऐसा लगता है कि सरकार ने ब्याज और जुर्माने की राशि इसलिए नहीं जाने दी क्योंकि ऐसे निर्णय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नजर में आ जाते हैं और बाद में ऐसे राजनीतिक विवादों को जन्म देते हैं कि निजी दूरसंचार कंपनियों का पक्ष लिया गया। सरकार द्वारा जुर्माने और ब्याज पर जोर देने की एक वजह यह भी है कि उसे अतिरिक्त राजस्व की जरूरत है ताकि राजस्व कमी दूर की जा सके।

ब्याज और जुर्माने सहित समूची राशि चुकाने पर जोर देने का अर्थ यह भी है कि वोडाफोन आइडिया जैसी दूरसंचार कंपनियों पर दो अन्य बड़ी कंपनियों की तुलना में अधिक असर होगा। कंपनी का सकल बकाय 50,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। कंपनी कह चुकी है कि इतनी बड़ी राशि चुकाना उसके बस की बात नहीं है और उसे अपना कारोबार समेटना पड़ेगा।

क्या सरकार ने इस निर्णय के नफा-नुकसान का आकलन किया है? जबकि इसका बोझ देश की तीन सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनियों में से एक को उठाना पड़ेगा? क्या उसे दूरसंचार बाजार ढांचे पर इस निर्णय के असर का आकलन करना चाहिए था? अंत में क्या सरकार ने यह समझा कि वोडाफोन आइडिया को इससे गहरा झटका लगेगा। यह कंपनी देश में 55 अरब डॉलर से अधिक का निवेश कर चुकी है। सरकार दूरसंचार क्षेत्र के लिए बेल आउट पैकेज ला सकती है ताकि वह मौजूदा भुगतान संकट से उबर सके। परंतु देश के निजी क्षेत्र पर इसका गहरा असर होगा।

मई 2019 के आम चुनाव में सत्ता में वापसी के बाद मोदी सरकार विदेशी निवेशकों के साथ दो बड़े मामलों में संबद्ध रही। एक मामला एमेजॉन के जेफ बेजोस से संबंधित है, जिनकी विदेशी निवेश संबंधी प्रतिबद्धताओं का सरकार के प्रतिनिधियों ने उपहास उड़ाया था। दूसरा मामला वोडाफोन आइडिया का है जिसका विदेशी साझेदार ब्रिटेन का वोडाफोन समूह एजीआर के बोझ तले दबा है। तीसरा मामला आने वाले महीनों में सुर्खियां बटोर सकता है। यह मामला है केयर्न एनर्जी और भारत सरकार के बीच 1.6 अरब रुपये के कर विवाद का जिस पर निर्णय आना है। किसी को नहीं पता कि यह मामला क्या मोड़ लेगा। परंतु कारोबारी सुगमता में सुधार पर गर्व करने वाले देश के लिए तीन बड़ी विदेशी कंपनियों एमेजॉन, वोडाफोन और केयर्न को प्रभावित करने वाला घटनाक्रम शायद भविष्य में इस सूचकांक में सुधार की संभावनाओं को प्रभावित करे।

कानाफूसी

लाज बचाने की जुगत

भारत यात्रा पर आए अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं की उपस्थिति में पत्रकारों के लिए भी एक बड़े शामियाने के नीचे दर्जनों कुर्सियां लगाई गई थीं। विदेश मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि साझा संवाददाता सम्मेलन में कोई सवाल करने की इजाजत नहीं होगी। जब तक कार्यक्रम शुरू हुआ। ज्यादातर पत्रकारों को पता चल गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति शाम को एक होटल में पत्रकारों के सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इससे हैदराबाद हाउस में शर्मिंदा करने वाले हालात बन गए क्योंकि अधिकांश पत्रकार वहां से उस होटल चले गए। आखिरकार सादी वर्दी में वहां घूम रहे सुरक्षाकर्मियों को कुर्सियों पर बिठाकर उन्हें भरा गया ताकि उपस्थिति सम्मानजनक नजर आए और लाज बच सके।

विचित्र अनुरोध

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय को अक्सर ऐसे अनुरोध मिलते हैं जिनमें कहा जाता है कि कला के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बच्चों पर विचार किया जाए। परंतु मंत्रालय के लोग इस बात से चकित हैं कि एक केंद्रीय मंत्री की बेटी के नृत्य कार्यक्रम करवाने के अनुरोध बार-बार उसके सामने आ रहे हैं। अटकलें तो यह हैं कि उसके पिता उसे राजनीति में करियर बनाने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन अधिकारी इस बात को लेकर सोच में पड़े हैं कि क्या नृत्य कार्यक्रमों के आयोजन से इसमें कुछ मदद मिल पाएगी?

आपका पक्ष

भारत अमेरिका के बीच कारोबारी संबंध

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप दो दिवसीय भारत की यात्रा पर आए और अपने कारोबारी हित साधते हुए विवादों से दूरी बनाकर वापस लौट गए। अमेरिका ने विश्व के शक्तिशाली देश के रूप में अपनी पहचान कायम की है तथा रूस, फ्रांस इसके प्रतिस्पर्धी देश हैं। भारत के अमेरिका, रूस तथा फ्रांस से संबंध बेहतर रहे हैं और इनके बीच संबंधों में कभी किसी देश ने आपत्ति भी नहीं जताई है। भारत रूस, फ्रांस तथा अमेरिका से सैन्य उपकरण खरीदता है तथा इसके अलावा अन्य तकनीकी उत्पादों का भी आयात करता है। भारत इन देशों के साथ सैन्य अभ्यास भी करता है लेकिन उन देशों के किसी अन्य देशों के बीच युद्ध की स्थिति में भारत शुरू से ही निर्गुट देश बन जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से 10 गुना कम है। भारत ने 5 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भारत पुरजोर

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप दो दिवसीय दौरे पर भारत की यात्रा पर आए थे

कोशिश भी कर रहा है। लेकिन भारत को रूस, फ्रांस तथा अमेरिका के समक्ष खड़े होने में कई वर्ष लगेंगे। अमेरिका तकनीक के मामले में दूसरे देशों से काफी आगे है। लेकिन भारत आज भी तकनीक के क्षेत्र में तीनों देशों से काफी पीछे है। भारत उन देशों से तकनीक का आयात भी करता है। इसके अलावा देश की खराब नीति के कारण भारतीय वैज्ञानिक यहां रहना नहीं चाहते हैं। उन्हें अमेरिका बेहतर अवसर प्रदान करता है जिससे वैज्ञानिक वहां चले भी जाते हैं। चाहे वह नासा का काम हो या माइक्रोसॉफ्ट का। ऐसे में देश की प्रतिभा पलायन कर जाती है तथा तकनीक उन देशों में विकसित हो जाती है जिनके निर्माता भले ही भारतीय वैज्ञानिक ही हों। बहरहाल भारत को अमेरिका से तथा नेताओं को ट्रंप से सीख लेनी चाहिए। ट्रंप ने भारत की यात्रा के दौरान अपने कारोबारी हित साध लिए। दोनों देशों के बीच कई सौदों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। ट्रंप ने भारत में अपने सौदे तो कर लिए लेकिन वह संवाददाता सम्मेलन में भारत के आंतरिक तथा बाह्य विवादों से दूर ही नजर आए जो एक सफल कारोबारी के गुण को प्रदर्शित करता है। भारत को अमेरिका से सीख लेकर कमियों को दूर करने तथा विकास की राह पर चलने की सीख लेनी चाहिए। जिससे भारत भी आने वाले वर्षों में विश्व में अपनी एक पहचान स्थापित कर सके।

पंकज कुमार, नई दिल्ली

दिल्ली से अन्य राज्य भी ले रहे सबक

अगर दिल्ली मॉडल को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनता के सामने जाते हैं तो उनके लिए बढ़ती जन अपेक्षा तथा लोकलुभावन नीतियों में तालमेल बिठाना आसान नहीं होगा। केजरीवाल की मुफ्त वाली योजनाओं को पूरे देश में लागू कर पाना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है। फिर भी राजनीतिक हलकों में इसकी संभावना तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री ने दिल्ली से संदेश ग्रहण करते हुए धीरे-धीरे हितकारी योजनाओं को अपने राज्यों में आजमाना शुरू कर दिया है। उदाहरण स्वरूप राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में मॉडल स्कूल की शुरुआत को लिया जा सकता है। शायद अब सभी नेताओं के मन में यह भाव आने लगा है कि हमें जनता से सीधे जुड़ने की जरूरत है।

अनुज नाथ तिवारी, गोरखपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

संक्षेप में

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आईसीएआर से करार

आईसीआईसीआई समूह की तरफ से सामाजिक दायित्व के कार्य के लिए गठित निकाय आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के साथ समझौता किया है। यह समझौता किसानों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए है। फाउंडेशन के बयान के अनुसार पिछले सप्ताह समझौते के तहत आईसीसीआई फाउंडेशन अपने ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के तहत आईसीए के ज्ञान और शोध का उपयोग करेगा और किसानों के लिए मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहतर करेगा। यह कार्यक्रम 29 राज्यों के ।,000 गांवों में चलाए जा रहे हैं। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा फाउंडेशन विभिन्न जिंसों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आईसीएआर के साथ नए पाठ्यक्रमों का आकलन करने के साथ उसे जरूरत के अनुसार तैयार करेगा। इसके अलावा दोनों भागीदार किसानों के फायदे के लिए तकनीकी ज्ञान साझा करने और प्रशिक्षण को बेहतर करने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। वे अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को भी आगे बढ़ाएंगे। फाउंडेशन ने अपने ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम के तहत 5,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया है। *भाषा*

दो खाद्य संस्थानों को राष्ट्रीय महत्त्व का दर्जा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हरियाणा और तमिलनाडु में दो राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान का दर्जा देने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी। कैबिनेट के फैसलों के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने दो खाद्य खाद्य संस्थानों को राष्ट्रीय महत्त्व का दर्जा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन (निफटेम) विधेयक, 2019 में संशोधनों को मंजूरी दी है। मंत्री ने कहा कि हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान को विशेष दर्जा प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से इन संस्थानों को विदेशी खाद्य संस्थानों के साथ सहयोग करने और शिक्षा के स्तर में सुधार करने में मदद मिलेगी। *भाषा*

कोरोनावायरस से इस्पात मांग प्रभावित

कीमत वृद्धि से बढ़ेगा दबाव

अदिति दिवेकर और टी ई नरसिम्हन
मुंबई/चेन्नई, 26 फरवरी

इस्पात कीमतों में इजाफा

- घरेलू इस्पात उत्पादकों ने नवंबर से कीमतों में लगातार इजाफा किया है
- जेएसडब्ल्यू स्टील ने 1 मार्च से 500-750 रुपये प्रति टन कीमत वृद्धि की योजना बनाई

स्टील के दाम

दिन	रुपये/टन
1 जनवरी 2019	42,157
1 फरवरी 2019	41,936
1 मार्च 2019	42,922
1 अप्रैल 2019	42,279
1 मई 2019	41,642
1 जून 2019	41,191
1 जुलाई 2019	39,136
1 अगस्त 2019	37794
1 सितंबर 2019	36,562
1 अक्टूबर 2019	35,056
1 नवंबर 2019	34,950
1 दिसंबर 2019	36,121
1 जनवरी 2020	38,547
वर्तमान	39,000

स्रोत- एडलवाइस सिक्योरिटीज

भले ही घरेलू इस्पात उद्योग मार्च में कीमत वृद्धि की तैयारी कर रहा है, लेकिन कोरोनावायरस की वजह से आपूर्ति में व्यवधान के बीच कमजोर मांग से घरेलू इस्पात कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।

चीन में घरेलू हॉट-रोल्ड कॉइल की कीमतें पिछले कुछ दिनों में 1,000 रुपये प्रति टन तक गिरकर 39,000 रुपये पर आ चुकी हैं। अक्टूबर 2019 में 35,000 रुपये प्रति टन पर आने से पहले कीमतें अक्टूबर 2018 में 48,000 रुपये प्रति टन की ऊंचाई पर थीं।

जेएसडब्ल्यू स्टील में निदेशक (वाणिज्यिक) जयंत आचार्य ने कहा, 'हम 1 मार्च से 500-750 रुपये प्रति टन की कीमत वृद्धि की संभावना तलाश रहे हैं, क्योंकि वैश्विक कोकिंग कोयले की कीमतें चढ़ी हैं और हम मार्च 2019 में कीमतों की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत पीछे हैं। इसलिए कीमतों में वृद्धि की गुंजाइश है।'

घरेलू इस्पात उत्पादकों ने नवंबर से कीमतों में लगातार इजाफा किया है। मुंबई के एक कारोबारी ने नाम नहीं बताने के अनुरोध के साथ कहा, 'उत्पादक मार्च से कीमतें बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि अंतत: कीमत वृद्धि को वापस लेना होगा, क्योंकि बाजार मौजूदा समय में ज्यादा कीमत वृद्धि की स्थिति में नहीं है।' इसके अलावा, कोरोनावायरस के प्रसार ने घरेलू वाहन कंपनियों के साथ साथ व्हाइट गुड्स निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल के चीन से आयात को प्रभावित किया है, जिससे घरेलू आपूर्ति श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है। स्टील यूजर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसयूएफआई) के अध्यक्ष निकुंज तुरखिया ने कहा, 'वाहन निर्माता कुछ खास कलपुर्जों के लिए चीन पर निर्भर हैं। लेकिन कोरोनावायरस की वजह से इन कलपुर्जों की खेपें भारत नहीं आ रही हैं। व्हाइट गुड्स कैटेगरी के संदर्भ में भी यही स्थिति है। इसलिए यहां मध्यवर्ती उत्पादों के लिए मांग प्रभावित हुई है।'

> जेपीसी के आंकड़े में कहा गया है कि कुल तैयार इस्पात आयात में चीन की भागीदारी समीक्षाधीन अवधि में 22 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत रह गई

उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि आर्थिक मंदी की वजह से भारत में इस्पात आयात पहले से ही कमजोर बना हुआ था और दिसंबर में कोरोनावायरस के प्रसार के बाद से यह लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है।

जॉइंट प्लांट कमेटी (जेपीसी) के आंकड़े के अनुसार, भारत ने अप्रैल-नवंबर के दौरान 50.7 लाख टन इस्पात का आयात किया था, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 5.3 प्रतिशत कम है।

जेपीसी के आंकड़े में कहा गया है कि कुल तैयार इस्पात आयात में चीन की भागीदारी समीक्षाधीन अवधि में 22 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत रह गई। अवधि में बिक्री में 19 प्रतिशत तक की कमी आई।

चीन से आयात में कमी की वजह से घरेलू लौह अयस्क कीमतों में भी गिरावट आई है।

एनएमडीसी की निवेशक रिपोर्ट के अनुसार, कोरोनावायरस के प्रसाद से लौह अयस्क कीमतें वैश्विक रूप से 125 डॉलर की ऊंचाई की तुलना में फरवरी 2020 के शुरू से गिरकर 83 डॉलर प्रति टन पर आ चुकी हैं।

एमके रिसर्च के विश्लेषकों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में लौह अयस्क कीमतें कमजोर बनी हुई हैं क्योंकि चीन में उत्पादन अल्पावधि में बढ़ने की संभावना नहीं है।

इस्पात के निर्माण के लिहाज से लौह अयस्क और कोकिंग कोयला दो प्रमुख कच्चे माल हैं। इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट ऐंड ग्रोथ (आईएनएसडीएजी) में महानिदेशक सुश्मि बनर्जी ने कहा, 'इस्पात उत्पादन की दर धीमी है जिससे कमजोर मांग परिदृश्य के बावजूद इन्वेंट्री में गिरावट आ रही है।' फरवरी के शुरू में, घरेलू इस्पात इन्वेंट्री 400,000 टन पर थी जो पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले कम है और अप्रैल के शुरू में दर्ज आंकड़े से लगभग 200,000 टन कम है। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जिंदल स्टील ऐंड पावर, सरकार के स्वामित्व वाली सेल और राष्ट्रीय इस्पात निगम प्रमुख घरेलू उत्पादक हैं।

राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन को मंजूरी

50,000 लोगों के कौशल विकास के लिए भी व्यवस्था

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 26 फरवरी

- इस मिशन का मकसद चिकित्सा और सैन्य जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयुक्त तकनीकी कपड़े तैयार करने वाले उद्योग में भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर पहुंचाना है
- भारतीय तकनीकी कपड़ा खंड का आकार अनुमानित रूप से 16 अरब डॉलर या 250 अरब डॉलर वाले वैश्विक बाजार का छह प्रतिशत है
- इस मिशन के तहत वार्षिक औसत वृद्धि दर का लक्ष्य 15 से 20 प्रतिशत और वर्ष 2024 तक घरेलू बाजार का आकार 40 से 50 अरब डॉलर रखा

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,480 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन को आज मंजूरी प्रदान की। चार वर्षीय यह मिशन वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान क्रियान्वित किया जाना है।

तकनीकी कपड़ा अत्याधुनिक कपड़े का वह खंड है जिसे अनुप्रयोगों के बड़े दायरे में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कृषि, सड़क, रेल पटरी, बुलेटप्रूफ और अग्निरोधी जैकेट तथा अत्यधिक ऊंचाई पर सैनिकों द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र आदि। इस मिशन का मकसद चिकित्सा और सैन्य जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयुक्त तकनीकी कपड़े तैयार करने वाले उद्योग में भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्थान पर पहुंचाना है।

भारतीय तकनीकी कपड़ा खंड का आकार अनुमानित रूप से 16 अरब डॉलर या 250 अरब डॉलर वाले वैश्विक बाजार का छह प्रतिशत है। सरकार के अनुसार भारत में तकनीकी कपड़े की पैठ का स्तर कम है। यह पांच से 10 प्रतिशत के दायरे में है, जबकि विकसित देशों में यह स्तर 30 से 70 प्रतिशत है। इस मिशन के तहत वार्षिक औसत वृद्धि दर का लक्ष्य 15 से 20 प्रतिशत और वर्ष 2024 तक घरेलू बाजार का आकार 40 से 50 अरब डॉलर रखा गया है।

तकनीकी कपड़ों का निर्यात मौजूदा करीब 14,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2021-22 तक 20,000 करोड़ रुपये करने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 तक निर्यात में सालाना 10 प्रतिशत औसत वृद्धि सुनिश्चित की जानी है। इस क्षेत्र में प्रभावी समन्वय और संवर्धन गतिविधियों के लिए तकनीकी कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद का गठन किया जाएगा।

इस मिशन के तहत तकनीकी कपड़ा क्षेत्र में 50,000 लोगों के कौशल विकास के लिए व्यवस्था की गई है। नौ मंत्रालयों में तकनीकी कपड़ों और 92 उत्पादों का प्रयोग अनिवार्य किया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रौद्योगिकी और सरकार के प्रयासों के साथ खास तौर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों (एमएसएमई) तथा तकनीकी कपड़ा क्षेत्र में प्रौद्योगिकीविदों के लिए नया भविष्य नजर आएगा। इससे भारत रक्षा और एयरोस्पेस जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होगा।

इसके अलावा कृषि, मत्स्य पालन, डेयरी, पोल्ट्री, जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत में तकनीकी कपड़ों के उपयोग से लागत में सुधार आएगा और पानी तथा मृदा संरक्षण बेहतर होगा। इससे कृषि उत्पादकता और प्रति हैक्टेयर किसानों की आय में भी इजाफा होने की उम्मीद है।

सरकार हरकत में, हालात नियंत्रण में

डोभाल ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सीसीएस को हिंसाग्रस्त इलाकों की स्थिति की जानकारी दी

बीएस संवाददाता

दिल्ली में कानून व्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को लेकर उच्च न्यायालय ने सरकार को स्पष्ट दिशानिर्देश दिए वहीं हिंसा प्रभावित इलाकों में निजी स्तर पर जमीनी हालात का मुआयना करने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने बुधवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) को सांप्रदायिक दंगे के शिकार हुए इलाकों की स्थिति के बारे में अवगत कराया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति बनाए रखने की अपील की जिसके बाद अब हिंसाग्रस्त इलाके में स्थिति फिलहाल थोड़ी नियंत्रण में दिख रही है।

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) जिसे आमतौर पर भारत-नेपाल सीमा पर तैनात किया जाता है और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) जैसे सुरक्षा बलों ने दंगा प्रभावित क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया और निवासियों को घर में रहने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में दंगों के कारण अब तक करीब 22 लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें एक खुफिया ब्यूरो (आईबी) के एक अधिकारी की मौत भी शामिल है। हिंसाग्रस्त इलाके में कई परिवारों ने दोबारा हिंसा छिड़ने के डर से स्थिति के सामान्य होने तक अपने घर को बंद कर दूसरी जगह चले गए हैं। हिंसाग्रस्त इलाकों का जायजा लेने से यह अंदाजा मिलता है कि दंगे में कुछ चुनिंदा दुकानों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से शांति और भाइचारा बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि वे कानून को अपने हाथों में न लें। हालांकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार को कई दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि दंगे में मारे गए मृतकों का अंतिम संस्कार करते वक्त पूरी गरिमा बनाए रखी जाए, हिंसाग्रस्त इलाके में निवासियों को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही कई बार चौबीस घंटे पीड़ितों को टेलीफोन हेल्पलाइन की सुविधा और पर्याप्त निगरानी का इंतजाम किया जाए। अदालत ने सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे नफरत फैलाने वाले भाषणों के वीडियो सुनें। इसके अलावा अदालत ने दिल्ली पुलिस से शुक्रवार तक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद प्रवेश शर्मा, भाजपा नेता कपिल मिश्रा और दिल्ली के भाजपा विधायक अभय वर्मा के उन भाषणों का संज्ञान लेने के लिए कहा जिसे उन्होंने पिछले कुछ हफ्ते के दौरान दिए हैं और आवश्यक होने पर भड़काऊ भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने को भी कहा।

न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भम्भानी के एक खंडपीठ ने राज्य और केंद्र सरकार के प्रभावशाली लोगों को पीड़ितों और उनके परिवारों से निजी तौर पर मुलाकात करने के लिए कहा। पीठ ने कहा, 'हम एक और 1984 (सिख विरोधी दंगे) की इजाजत नहीं दे सकते। खासकर अदालत और आपकी (दिल्ली पुलिस) की निगरानी में।' अदालत ने खुफिया ब्यूरो के एक अधिकारी की उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में मारे जाने की खबरों पर चिंता जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अदालत ने कहा कि पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन डेस्क बनाए जाएं और पीड़ितों को सुरक्षित अस्पताल ले लाने के लिए प्राइवेट एंबुलेंस का इंतजाम किया जाना चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि इस वक्त लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें आश्वस्त करना जरूरी है और यह जितनी जल्दी संभव हो किया जाना चाहिए। अदालत ने पीड़ितों को रखने के लिए आश्रय स्थल बनाने के साथ-साथ कंबल, दवाइयां, खाना और शौचालय से जुड़ी जरूरी सुविधाएं देने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि रात्रि शिविर और सामुदायिक हॉल का इस्तेमाल भी इस काम के लिए किया जा सकता है।

साथ में एजेंसियां

बुधवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित खजूरी खास क्षेत्र का नजारा (पीटीआई)

शीर्ष अदालत ने की पुलिस की खिंचाई

उच्चतम न्यायालय ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा पर पेशेवर तरीके से रोक लगाने में विफल रहने के लिए पुलिस की बुधवार को खिंचाई की। हालांकि, न्यायालय ने नए संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के मुद्दे पर हुए दंगों से संबंधित याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा, 'अगर कोई भड़काऊबयान देता है तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।'न्यायालय ने यद्यपि हिंसा से संबंधित आवेदनों पर विचार नहीं किया लेकिन कहा कि शाहीन बाग में प्रदर्शन से संबंधित मामलों पर सुनवाई के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण की जरूरत है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ के पीठ ने कहा कि वह हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर विचार कर शाहीन बाग प्रदर्शनों के संबंध में दायर की गई याचिकाओं का दायरा नहीं बढ़ाएगी। पीठ ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय करते हुए कहा कि शाहीन बाग मुद्दे पर सुनवाई से पहले उदारता और स्थिति के शांत होने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन वे सड़क को बाधित नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए वार्ताकारों की नियुक्ति के जरिये परंपरा से हटकर समाधान निकालने का प्रयास किया।

अमित शाह दें इस्तीफा: सोनिया

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा को सुनियोजित षड्यंत्र का नतीजा बताते हुए इसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक में दिल्ली के हालात पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुईं सोनिया गांधी ने केंद्र, गृह मंत्री और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के कई नेताओं ने बयान से डर एवं नफरत का माहौल पैदा किया।।

सोनिया ने सीडब्ल्यूसी में पारित प्रस्ताव पढ़ा जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली सरकार भी शांति-सद्भाव बनाए रखने में नाकाम रही तथा केंद्र व राज्य सरकारों की जिम्मेदारी निभाने में विफलता के कारण देश की राजधानी इस त्रासदी का शिकार बनी है। उन्होंने कहा कि सरकार को शांति बहाली और पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहते हुए ऐसी परिस्थितियों में सर्वदलीय बैठकें बुलाते थे पर दुर्भाग्य से इस सरकार में ऐसा नहीं हो रहा। सीडब्ल्यूसी में सवाल किया गया, 'पिछले रविवार से देश के गृहमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां थे और क्या कर रहे थे? खुफिया एजेंसियों की जानकारी पर क्या कार्रवाई हुई? जब हालात बेकाबू हो गए थे व पुलिस का नियंत्रण नहीं था तब ऐसे में और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को क्यों नहीं बुलाया गया?'

बचपन में इतिहास पढ़ना पसंद था सत्य नडेला को

नेहा अलावधी

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला अब विश्व की सबसे बड़ी तकनीक कंपनियों में से एक की अगुआई कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्कूल के दिनों में इतिहास पढ़ने में गहरी रुचि थी। नडेला ने नई दिल्ली में बुधवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी के कुछ सवालों के जवाब दिए। हालांकि स्कूल के दिनों में उनका पसंदीदा विषय इतिहास था और उन्हें पुस्तकों से प्रेम है। जब उनसे यह पूछा गया कि उनके पसंदीदा क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर हैं या विराट कोहली तो उन्होंने सुरक्षित रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि इनमें से किसी एक का चुनाव धर्म चुनने जितना कठिन है। उन्होंने नपा-तुला जवाब दिया, 'मैं कहूंगा कि कल सचिन और आज विराट।'

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ नडेला का जन्म भारत में हुआ था। वह इस समय भारत के दौरे पर आए हुए हैं। वह अपने इस दौरे में कारोबारी नेताओं और मुंबई, बेंगलूरु और नई दिल्ली में तकनीक जगत से जुड़े पेशेवरों से मिले हैं। नडेला बुधवार दोपहर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद से भी मिले। इस बैठक के बाद प्रसाद ने ट्वीट किया, 'माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के सीईओ के साथ मुलाकात अच्छी रही। उनके साथ डिजिटल इंडिया की सफलता की कहानियां साझा कीं और आईटी क्षेत्र से जुड़े व्यापक मुद्दों के बारे में बातचीत की।' नडेला युवा नवोन्मेषी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली आए हुए थे। इस सम्मेलन में दिल्ली-एनसीआर के 250 से अधिक छात्रों और शिक्षकों ने हिस्सा लिया।

जब नडेला से पूछा गया कि वह कौनसी सुपर पावर प्राप्त करना चाहेंगे तो उन्होंने कहा, 'अगर मैं उन सभी किताबों को पढ़ सकूं, जो मैंने खरीदी हैं तो मैं बहुत बेहतर स्थिति में होऊंगा...यही वजह है कि मैं स्वाभाविक भाषाई प्रगति को लेकर उत्साहित हूं।' उन्होंने उन दो अहम रुझानों के बारे में भी बातचीत की, जो भविष्य में आवश्यक कंप्यूटर ताने-बाने को परिभाषित करेंगे।

उन्होंने कहा कि 2030 तक 50 अरब डिवाइस आपस में जुड़े होंगे, जो अधिकतम स्तर होगा। दूसरी ओर वर्ष 2025 तक डेटा सृजन चौगुना यानी 175 जेटा बाइट (जेडबी) हो जाएगा।

माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष प्रमुख ने कोडिंग के बारे में भी बातचीत की। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कोडिंग को चुनेंगे या क्रिकेट को तो उन्होंने कहा, 'क्रिकेट के लिए कोडिंग।'

उन्होंने अनिल कुंबले का उदाहरण दिया, जिनकी स्टार्टअप क्रिकेट बैट में सेंसर के जरिये आईओटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल कर रही है। वहीं नारायण हेल्थ के संस्थापक डॉ. देवी शेट्टी का उदाहरण दिया, जो डेटा एनालिटिक्स का व्यापक इस्तेमाल करते हैं। नडेला ने कहा, 'कोडिंग आपको कला और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में कुछ अलग करने के लिए प्रेरित कर सकती है।'

नडेला 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बने थे और तब से इस कंपनी का बाजार पूंजीकरण करीब पांच गुना बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर से अधिक हो चुका है। उन्होंने क्लाउड जैसे खंडों पर बड़ा दांव लगाया है माइक्रोसॉफ्ट को इस खंड की बाजार अगुआ माना जाता है। कंपनी भारत में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जिसका मुख्य जोर अजुरे (क्लाउड कारोबार), कृत्रिम मेधा, स्टार्टअप, ऑफिस365 और सरकारी साझेदारियों पर है।

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला इस वक्त भारत दौरे पर आए हैं

दुनिया के अमीरों में मुकेश अंबानी 9वें पायदान पर

हुरुन की विश्व के धनी व्यक्तियों की सूची में शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय मुकेश अंबानी हैं। वह इस सूची में 9वें पायदान पर रहे हैं। एमेजॉन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस लगातार तीसरे साल शीर्ष पायदान पर रहे हैं।

मुकेश अंबानी भारत ही नहीं एशिया में भी सबसे धनी हैं। उनकी संपत्ति में 24 फीसदी या 13 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसमें उनके दूरसंचार कारोबार के अच्छा प्रदर्शन करने की अहम भूमिका रही है। हुरुन की सूची में शीर्ष 10 में से सात धनी अमेरिका के हैं। देश में बैंकर उदय कोटक काफी सम्मानित व्यक्ति हैं और आम तौर पर उनका नाम धनी लोगों की सूची में शामिल होता रहता है। हालांकि यह विशेष मौका है। हुरुन की धनी लोगों की वैश्विक सूची 2020 के मुताबिक, '1,04,300 करोड़ रुपये के नेटवर्थ के साथ कोटक शीर्ष 100 अमीरों में शामिल हो गए हैं, जिससे वह विश्व में सबसे अमीर सेल्फ-मेड बैंकर बन गए हैं।'

पिछले साल चीन में अमेरिकी तुलना में तीन गुना नए अरबपति बने। चीन में कोरोनावायरस फैलने के बाद वहां दवा एवं ऑनलाइन मनोरंजन क्षेत्र में कारोबारियों ने तगड़ी कमाई की। हॉन्ग-कॉन्ग और ताइवान समेत वृहद चीनी क्षेत्र में 31 जनवरी को समाप्त वर्ष में 182 नए अरबपति बने, जिससे यहां कुल अरबपतियों की संख्या बढ़कर 799 हो गई। इसकी तुलना में अमेरिका में 59 नए अरबपति बने।

जेफ बेजोस की अनुमानित संपत्ति 140 अरब डॉलर है, जो पिछले साल की तुलना में सात अरब डॉलर घटी है। हुरुन की इस सूची में दुनियाभर के उन 2,817 लोगों को शामिल किया गया है, जिनकी संपत्ति एक अरब डॉलर या उससे अधिक है।

एजेंसियां

मुकेश अंबानी एशिया में भी सबसे अमीर हैं

महिला नेतृत्व को लेकर संशय बरकरार

अमृता पिल्लई

सरकार या किसी प्रमुख कंपनी की अगुआ महिला होने पर हर 10 भारतीयों में से चार से भी कम बहुत सहज महसूस करते हैं। अनुसंधान सलाहकार कंपनी कैंटर के एक शोध में यह बात सामने आई है। इसके अलावा भारत और दुनियाभर में महिलाएं पुरुषों की तुलना में शीर्ष पदों पर महिलाओं को ज्यादा स्वीकार कर रही हैं।

पहली बार भारत को कैंटर के इस सालाना सर्वेक्षण में शामिल किया गया है। इसमें देशों को इस आधार पर रेटिंग दी जाती है कि सभी क्षेत्रों में अगुआ के पदों पर उपयुक्तता के लिहाज से पुरुषों और महिलाओं को कितना समान माना जाता है। इस सर्वेक्षण को रेकजविक अगुआ सूचकांक नाम दिया गया है। इसमें इस साल जी7 देशों और ब्रिक्स देशों को शामिल किया गया है। यह सूचकांक 0 से 100 तक है। स्कोर 100 होने का मतलब है कि पूरा समाज यह मानता है कि सभी क्षेत्रों में नेतृत्व के लिए महिला एवं पुरुष समान रूप से उपयुक्त हैं। कैंटर की बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है, 'भारत और ब्राजील के सूचकांक जी7 देशों में कम स्कोर वाले देशों (इटली 68, जर्मनी 69 और जापान 70) के समान हैं, जबकि रूस तथा चीन और नीचे हैं।' भारत की रैंकिंग 67 है। इस रैंकिंग में ज्यादा ऊपर होने का मतलब है कि वह देश अगुआई के पदों पर पुरुषों और महिलाओं को ज्यादा स्वीकार करता है।

वर्ष 2019 के रेकजविक अगुआ सूचकांक में विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकार्यता को भी मापा गया है। सर्वेक्षण के नतीजे यह संकेत भी देते हैं कि भारत में रक्षा क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं दोनों की स्वीकार्यता वैश्विक औसत से अधिक है। भारत का रक्षा एवं पुलिस का सूचकांक 68 था, जो जी7 देशों के समग्र सूचकांक 62 से अधिक था।

इस सर्वेक्षण के तहत कैंटर ने ग्रामीण और शहरी भारत में 5,000 लोगों से पूछा कि वे सरकार के प्रमुख और किसी प्रमुख कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी के रूप में महिलाओं को स्वीकार करने में कितना सहज महसूस करेंगे। भारत में 39 फीसदी लोगों ने कहा कि वे सरकार का प्रमुख महिला होने पर बहुत सहज महसूस करेंगे। यह उन 34 फीसदी लोगों से अधिक है, जिन्होंने किसी कंपनी की प्रमुख महिला होने को लेकर 'बहुत सहज' होने के बारे में कहा। हालांकि ऐसी नियुक्तियों के लिए पुरुष कम स्वीकार्य हैं। हालांकि सरकार और राजनीति में राजनेताओं के रूप में पुरुष और महिलाओं की समग्र स्वीकार्यता में भारत की रैंकिंग ऊंची रही। रिपोर्ट में कहा गया, 'भारत में इस क्षेत्र का सूचकांक स्कोर 74 था, जहां इंदिरा गांधी दो बार 1966 से 1977 तक और 180 से 194 तक प्रधानमंत्री और प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 के बीच राष्ट्रपति रह चुकी हैं। इस समय भारतीय संसद के सदस्यों में 14 फीसदी महिला हैं।'

महिला सीईओ की नियुक्ति पर 10 में से चार भारतीय ही सहज

लोग कितने सहज..	भारत	भारत (पुरुष)	भारत (महिला)	कनाडा	रूस	जर्मनी
सरकार के प्रमुख के रूप में महिला	39	34	44	59	8	31
बड़ी कंपनी के सीईओ के रूप में महिला	34	30	37	62	11	33

स्रोत : कैंटर का 2019 में नेतृत्व के लिए रेक्जविक सूचकांक

एशिया में बढ़ रहे कोरोनावायरस संक्रमण के मामले

एशिया में बुधवार को कोरोनावायरस संक्रमण के सैकड़ों नए मामले की पुष्टि हुई है जिनमें दक्षिण कोरिया में तैनात अमेरिका का एक सैनिक भी शामिल है जो इस वायरस से संक्रमित पाया गया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि यह महामारी ईटली और ईरान से बढ़कर दूसरे देशों में भी फैल सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि अब चीन के भीतर से ज्यादा, चीन के बाहर से रोजाना कोरोना वायरस के अधिक मामले सामने आ रहे हैं।

बाजार में हलचल

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लंबे समय तक बाधित रहने के डर की वजह से दुनिया भर के शेयर पांचवें दिन भी गिरे जबकि निवेश के लिए सुरक्षित माने जाने वाला सोना सात साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है जबकि अमेरिका बॉन्ड का प्रतिफल रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। एमएससीआई ऑल कंट्री इन्डेक्स के मुताबिक पिछले चार कारोबारी सत्र के दौरान वैश्विक स्तर के शेयर बाजार ने 3.3 लाख करोड़ डॉलर गंवाएं हैं।

कोरोनावायरस की यह महामारी चीन के एक शहर वुहान के वन्यजीवों की बिक्री करने वाले बाजार से पिछले साल फैली और इससे जीन में करीब 80,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और 2,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका के रोग नियंत्रक एवं निरोधक केंद्र ने संक्रमण की आशंका को देखते हुए अमेरिका के लोगों को तैयार रहने के लिए कहा है। अमेरिका में वायरस के 57 मामले सामने आए हैं। भारत यात्रा से अमेरिका वापस लौटे अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि वह कोरोनावायरस पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। डब्ल्यूएचओ-चीन के संयुक्त अभियान के प्रमुख डॉक्टर ब्रूस आइलवॉर्ड ने संवाददाताओं से कहा कि सभी देशों को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, 'वायरस का संक्रमण अगले ही दिन हो सकता है। अगर आप इस तरह नहीं सोचेंगे तब आप तैयार नहीं हो सकते हैं।'

कुआलालंपुर हवाईअड्डे पर महिला की स्वास्थ्य जांच

चीन के हालात

चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि हुबेई से 52 लोगों की मौत की खबर मिली है और देशभर में कोरोनावायरस के 406 नए मामले सामने आए हैं। इसमें कहा गया कि मृतक आंकड़ा 2,715 पर पहुंच गया और संक्रमण के कुल पुष्ट मामलों की संख्या 78,064 हो गई। दक्षिण कोरिया के देगू में 169 में से 134 नए मामलों की पुष्टि हुई है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 60 साल के एक व्यक्ति की कोरोनावायरस से मौत हो गई है। कोरोना वायरस से फ्रांसीसी नागरिक की यह पहली मौत है। स्वास्थ्य मंत्रालय के उप प्रमुख जेरोम सलोमोन ने बताया इस मौत से वायरस के कारण देश में मरने वालों की संख्या बढ़ कर दो हो गई। फ्रांस में पिछले 24 घंटे में चार और लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से दो इटली से वापस लौटे हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ कर 17 हो गई है।

एजेंसियां